



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

No. 203]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 1997/ज्येष्ठ 7, 1919

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 1997/JYAISTHA 7, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पल्लग पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1997

सा. का. नि. 281 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

(अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1997

भविष्य निधि तथा उपदान से संबंधित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट विनियम का अधिक्रमण करते हुए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्ष :

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1997 के नाम से कहलाए जाएंगे।

2. प्रयोजन :

ये विनियम बोर्ड की सेवा के लिए नियुक्त सभी व्यक्तियों तथा जो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि में शामिल किए गए हैं, के लिए लागू होंगे।

3. परिभाषा :

(1) इन विनियमों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :—

1. “लेखा अधिकारी” से तात्पर्य है, बोर्ड के विशेष सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा विनिर्धारित लेखा विभाग के उस अन्य अधिकारी से है ।
2. “अधिनियम” से तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) से है ।
3. “बोर्ड” से तात्पर्य अधिनियम के तहत नियुक्त मद्रास पोर्ट के न्यासियों से है ।
4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्षों का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम के तहत दिया गया है ।
5. “अंशदान” से तात्पर्य इन विनियमों के तहत अंशदाता के खाते में बोर्ड द्वारा किए गए अंशदान तथा विशेष अंशदान से है ।
6. इन विनियमों के तहत विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ “आश्रित” से तात्पर्य निधि को अंशदान करने वाले उस मृतक व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से किसी एक से है अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता, बच्चा, अवस्थक भाई, अविवाहित बहन तथा मृतक बेटे की पत्नी या बच्चा तथा उन मामलों में जिनमें अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो दादा-दादी ।
7. “परिलिंग्यां” :

(ए) वर्ग-1 व 2 के अधिकारियों के संबंध में परिलिंग्यां से तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन या निर्धार्ह-अनुदान केन्द्र सरकार की मौलिक नियमावली में बताए अनुसार होगा या अगर कोई विनियम बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो तथा निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाने वाला नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल होगा लेकिन सवारी भत्ता, आवास किराया भत्ता, समयोपरि शुल्क, सीमेंट टेस्टिंग भत्ता, फ्लोरिंग क्राफ्ट के पर्यावरण के लिए शुल्क, डाइविंग भत्ता, मानदेव शुल्क किसी भी रूप में अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता आदि शामिल नहीं होंगे ।

(बी) वर्ग-3 व 4 के टाइम रेटेड कर्मचारियों के संबंध में परिलिंग्यां से तात्पर्य वेतन, छुट्टी वेतन या निर्धार्ह अनुदान केन्द्र सरकार की मौलिक नियमावली में बताए अनुसार होगा या अगर कोई विनियम बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो तथा मंहगाई भत्ता तथा कास्ट इन्डेक्स से जुड़े अन्य भत्ते जो भी इस प्रयोजन हेतु समय समय पर दिए जाएं तथा जिनकी गणना की जाए तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल हैं, लेकिन आवास किराया भत्ता, समयोपरि, रात्रि वरीयता, रविवार, छुट्टी के दिन तथा ऑफ दिन आदि पर कम काम करने के लिए सामान्य वेतन से अतिरिक्त, वेतन, जिसे वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, आदि शामिल नहीं होंगे ।

(सी) वर्ग-3 तथा 4 के पीस रेटेड तटीय श्रमिकों कर्मचारियों के संबंध में उनके वास्तविक उपार्जन, आइडियल टाइम वेतन, इवेशन भत्ता आदि शामिल होंगे । लेकिन पूरा आवास किराया भत्ता जो पीस रेट उपार्जन तथा अन्य भत्ते जो उपरोक्त (बी) में बताया गया है, शामिल नहीं होगा ।

(डी) विनियम 12 (3) तथा (5) के तहत किए जाने वाले विशेष अंशदान तथा देय अतिरिक्त राशि के प्रयोजनार्थ ।

वर्ग-1 व 2 के कर्मचारियों के संबंध में परिलिंग्यां से तात्पर्य है, वेतन जो मौलिक नियमावली 9 (21) में बताया गया हो या अगर कोई विनियम बोर्ड द्वारा बनाया गया है तो जो भी लागू हो वह तथा अन्य कोई वेतन जो वेतन के रूप में समय समय पर निर्धारित व वर्गीकृत किया गया हो, जिसे वर्ग-1 या वर्ग-2 के अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहे हों तथा निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाने वाला नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल होगा ।

वर्ग-3 तथा 4 के कर्मचारियों के संबंध में परिलिंग्यां से तात्पर्य है, मौलिक नियमावली 9 (21) के तहत बताया गया वेतन मंहगाई भत्ता तथा समय समय पर वेतन के रूप में वर्गीकृत व स्थीकृत की गई अन्य कोई राशि प्रोत्साहन उपार्जन तथा जहाँ कहीं लागू हो वहाँ रिजल्ट योजना द्वारा भुगतान के तहत अन्य ऐसे भुगतान से है ।

स्पष्टीकरण :

पीस रेटेड कर्मचारियों के संबंध में विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ वेतन से तात्पर्य है । कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़ने या उसकी मृत्यु होने की तारीख से पहले वाले 12 माहों के दौरान मासिक औसत परिलिंग्यां से है । बिना वेतन के अनुपस्थिति की अवधि को इस गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा । अधिनियम के अनुसार उपदान का भुगतान प्राप्त करने वाले उन कर्मचारियों के संबंध में औसतन परिलिंग्यां हेतु परिलिंग्यां वाली वर्ग लागू नहीं होगी जिन्हें उपदान अधिनियम 1972 के तहत उपदान का भुगतान किया जाता है ।

नोट :

- (1) अधिवर्यता की तारीख के पूर्व सेवानिवृत्ति के तैयारी के लिए छुट्टी के दौरान अंजित वेतन वृद्धि, जब कि वह वास्तविक में नहीं ली गयी है, को विशेष अंशदान के प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में माना जाएगा ।

(2) उस मामले में जहां कर्मचारी के छुट्टी पर रहते वक्त चिकित्सा अयोग्य सामित कर दिया जाता है या छुट्टी पर रहते वक्त मृत्यु हो गई तो, ऐसी छुट्टी के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि, जिसका वास्तव में भुगतान नहीं किया गया है, को विशेष अंशदान के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपरोक्त नोट (1) तथा (2) में बताए गए वेतन वृद्धि से तात्पर्य है, वेतन वृद्धि, वेतनमान में संशोधन आदि से वेतन में उत्पन्न वृद्धि से है ।

8. कर्मचारी

स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी शब्द का जो अर्थ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति/पदोन्नति) आदि, विनियम में दिया गया है, वही होगा ।

9. “परिवार” से तात्पर्य :

(ए) पुरुष अंशदाताओं के मामले में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे तथा जिस मामले में अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हों तो दादा-दादी ।

बशर्ते कि अगर अंशदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी बीमी कानूनी रूप से उससे अलग हो गई है या वह जिस समुदाय की है के सामाजिक विवाजी नियम के तहत वह अनुरक्षण के लिए हकदार नहीं है तो इस विनियम के संबंध में वह अंशदाता के परिवार की सदस्य नहीं होगी, जब तक कि अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में उसे परिवार के सदस्य के रूप में मानने के लिए लिखकर नहीं दे देता; तथा

(बी) स्त्री अंशदाता के मामले में, पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे तथा जिस मामले में अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हों तो दादा-दादी :

परन्तु अगर अंशदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने पति का नाम परिवार से निकालने के लिए देती है तो इस विनियम के संबंध में पति, किसी भी मामले में अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं होगा जब तक कि अंशदाता इसे रद्द करने के लिए लिखित रूप में नहीं देती ।

स्पष्टीकरण :

बच्चे में तात्पर्य है वैध बच्चा तथा गोद लिया हुआ बच्चा, जिसका गोद लेना अंशदाता के वैयक्तिक नियम द्वारा मान्यताप्राप्त हो, जो कर्मचारी के साथ रहता हो तथा परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, तथा जिसे कर्मचारी ने विशेष व्यवस्था द्वारा जन्म दिए हुए बच्चे के समतुल्य स्थान दिया हो ।

10. निधि से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि से है ।
11. छुट्टी से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट छुट्टी विनियम के तहत किसी भी प्रकार की छुट्टी से है ।
12. स्वीकृतिदाता से तात्पर्य इन विनियमों के प्रयोजनार्थ इस विनियम के साथ मंलग्न अनुसूची में निर्धारित के अनुसार होगा ।
13. इन विनियमों के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ “सेवा” से तात्पर्य सेवा में प्रवेश करने की तारीख से अंशदाता की लगातार सेवा में है । जिसमें भत्तों के साथ या भत्तों के बिना प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है तथा बिनांबोर्ड के वैतनिक शिक्षु की सेवा अगर बिना रुकावट के स्थाई सेवा होती है तो वह भी शामिल है । सेवा को माफ करना हरेक मामले में किसी भी सेवा की रुकावट की अवधि छः माह से ज्यादा न होने पर, अध्यक्ष अपने विवेकानुसार माफ कर सकते हैं बशर्ते कि हरेक रुकावट छः माह की लगातार सेवा के बाद हो ।
14. विशेष अंशदान से तात्पर्य अंशदाता के अंशदान खाते के विनियम 12 के तहत किए गए विशेष अंशदान से है ।
15. वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है ।

(2) इन विनियमों में प्रयोग की गई अन्य कोई अभिव्यक्ति भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19 वां) में या केन्द्र सरकार की मौलिक नियमावली में या ओर्ड द्वारा बनाए गए अन्य किसी विनियम में जिस अर्थ के लिए बनाया गया है उसी से है ।

4. निधि का गठन तथा प्रबंध :

- (1) निधि का प्रशासन बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा तथा भारत में रुपए के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा ।
- (2) इन विनियमों द्वारा ओर्ड लिखित रूप में संकल्प द्वारा यह निर्धारित केन्द्र कि इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग स्वीकृतिदाता द्वारा किया जाएगा । ऐसे किन्हीं संकल्पों को संशोधित या निरस्त करने को ओर्ड को अधिकार होगा ।

5. भविष्य निधि आरक्षण निधि :

(1) जब कभी निधि की प्रत्याभूतियां पूर्ण होती हैं या बेची जाती हैं, तब बोर्ड निम्न प्रक्रिया अपनाएगा :—

(ए) ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई लाभ होगा तो उसे भविष्य निधि आरक्षण निधि कहलाए जाने वाली आरक्षण निधि में जमा किया जाएगा ।

(बी) ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई नुकसान होता है तो भविष्य निधि आरक्षण निधि से पूरा किया जाएगा ।

(2) बोर्ड यह भी करेगा कि :—

(ए) अगर जब कभी “भविष्य निधि” आरक्षण निधि में कोई कमी उत्पन्न हुई तो उसे अपने राजस्व लेखे से पूरा किया जाएगा ।

(बी) ऐसा उप विनियम के प्रावधानों के तहत होगा ।

(सी) जब कभी यह आरक्षण निधि बंद कर दी जाती है तो उसके राजस्व लेखे के अंतिम शेष को भविष्य निधि आरक्षण निधि में जोड़ा जाएगा ।

नोट : उपरोक्त 1 अप्रैल, 1940 से लागू होगा ।

(3) किसी एक समय भविष्य निधि आरक्षण निधि लेखे में रखी जाने वाली अधिकतम राशि रुपए 10,000 (रुपए दस हजार) होगी । इस सीमा से अधिक आने वाली राशि को राजस्व लेखे में जमा के रूप में स्थानान्तरित किया जाएगा ।

6. नामांकन :

(ए) लेखा अधिकारी किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर किसी भी अंशदाता के खाते में जमा राशि के देय होने से पहले अथवा अदायारी होने से पहले ऐसी राशि उसे देय हो गई हो, के मामले में, विनियम 12 के उप विनियम 3 व 5 के तहत ग्राहीय अंतिरिक्त राशि तथा विशेष अंशदान को छोड़कर जमा खाते में उक्त राशि के प्राप्त करने का प्राधिकार देते हुए उससे नामांकन भरवाएगा ।

(बी) निधि में शामिल होने वाला ऐसा अंशदाता जिसका परिवार हो तो लेखा अधिकारी को पहली अनुसूची में बताए गए फार्म में अपने परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों का नामांकन भेजेगा ।

(सी) अंशदाता जिसका कोई परिवार नहीं है तो वह दूसरी अनुसूची में बताए गए फार्म में किसी एक या कई व्यक्तियों का नामांकन भरेगा ।

ऐसा दिया गया नामांकन तब तक माना जाएगा जब तक कि अंशदाता का परिवार नहीं हो जाता ।

नोट: इस उप विनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यक्ति या व्यक्तियों में एक कम्पनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं शामिल होंगे ।

(डो) अंशदाता को नामांकन में यह प्रावधान करना होगा:—

(1) किसी विनिर्दिष्ट नामिती के सम्बन्ध में अंशदाता से पूर्व मृत्यु के मामले में उस नामिती को प्रदत्त अधिकार नामांकन में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति अंशदाता के परिवार का व्यक्ति या के व्यक्ति हों ।

(2) उसमें आकस्मिकता होने पर विनिर्दिष्ट नामांकन अमान्य हो जाएगा:—

बशर्ते कि नामांकन देते समय अंशदाता के कोई परिवार नहीं है तो उसको नामांकन में यह प्रावधान करना होगा कि उसके परिवार होने के बाद यह नामांकन अमान्य माना जाएगा ।

पुनः प्रावधान है कि नामांकन देते समय अंशदाता के परिवार में एक ही व्यक्ति है तो उसे नामांकन में यह प्रावधान करना होगा कि उसके परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों के आने के बाद खंड (1) के तहत वैकल्पिक नामिती को दिया गया अधिकार अमान्य जाएगा ।

(ई) उपरोक्त छोटी के खंड (1) के तहत ऐसे नामिती जिसके लिए नामांकन में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, की मृत्यु हो जाती है या उपरोक्त छोटी के खंड (2) के तहत या उसके प्रावधान के तहत किसी वजह से नामांकन अमान्य माना जाता है तो ऐसी स्थिति में अंशदाता इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अधिकारी को लिपित रूप में पुराना नामांकन रद्द करके नया नामांकन भेजेगा ।

(एफ) अंशदाता को विनियम 12 के उप विनियम (3) तथा (5) के तहत ग्राह्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि को छोड़कर नामांकन में निधि के तहत उसके खाते में रहने वाली राशि को अपने विवेकानुसार नामितियों में बॉट सकता है।

(जी) अंशदाता द्वारा नामांकन लिखित रूप में रद्द किया जा सकता है तथा इस विनियम के तहत दूसरा नामांकन दिया जा सकता है।

(एच) लेखा अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने पर ही नामांकन चालू रहेगा।

7. अंशदाता का लेखा:

हरेक अंशदाता के नाम एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा।

1. अंशदाता का अंशदान (अनिवार्य तथा स्वैच्छिक)
2. विनियम 15 के तहत प्रदत्त व्याज
3. अंशदान पर विनियम 17 के तहत प्रदत्त बोनस
4. निधि से भुगतान तथा बसूल तथा वापस किए गए सभी अग्रिम।
5. अंशदान
6. अंशदान पर व्याज

8. अंशदान की शर्तें:

(ए) इयूटी पर या विदेश सेवा पर रहते वक्त हरेक अंशदाता मासिक अंशदान करेगा निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं करेगा।

बशर्ते कि निलम्बन की अवधि के बाद अंशदाता के पुनः इयूटी पर आने पर उसको यह विकल्प दिया जाएगा कि निलम्बन की अवधि के दौरान के बकाया अंशदान को एक किश्त में या किश्तों में दे सकता है परन्तु वह राशि उस अवधि के लिए अनुमति राशि से अधिक नहीं होगी।

(बी) जब अंशदाता को विदेशी सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है या प्रतिनियुक्त पर विदेश भेजा जाता है तो, वह निधि के विनियम के तहत उसी रीति से रहेगा मानो कि वह स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त पर न भेजा हो।

(सी) कोई भी अंशदाता जो छुट्टी के दौरान या तो छुट्टी बेतन नहीं सेता है या छुट्टी बेतन अर्ध बेतन के समतुल्य या उससे कम है तो अंशदान न देने का विकल्प दे सकता है।

(डी) छुट्टी पर जाने से पहले अंशदाता को लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सूचना देगा कि उपरोक्त उप-खण्ड (सी) में सन्दर्भित छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं काटा जाए। समय पर सूचना न देने से अंशदान काटा जाएगा। इस उप विनियम के तहत अंशदाता द्वारा दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

9. अंशदान की दर

अंशदान की राशि अंशदाता द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों से विधेय हो:-

(ए) उसे पूर्णक में बतायी जाएगी

(बी) यह राशि परिसंचयों की या तो 8 1/3% (1-4-1993 से 10%) या कोई अन्य उच्च प्रतिशत राशि हो सकती है।

॥१॥ इस प्रकार निर्धारित अंशदान जो लेखा अधिकारी को एक माह के नोटिस से दिया हो, निम्न प्रकार से होगा:-

॥१॥ वर्ष में एक बार किसी भी समय कम किया हो ।

॥२॥ वर्ष में किसी एक बार बढ़ाया हो ।

॥३॥ उपरोक्त बतार अनुसार कम करने तथा बढ़ाने के लिए प्रावधान है कि कम करने वाली राशि खण्ड ॥बी॥ में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम न हो ।

॥४॥ अगर अंशदान की राशि पैसे में आती है तो उसे अगले पूर्णक में बदल दिया जाएगा ।

इस विनियम के प्रयोजनार्थ परिलक्षियों की गणना अंशदाता के ड्यूटी पर रहते वक्त मातिक भुगतान की दर से होगी ।

नोट: निलम्बन की अवधि के सम्बन्ध में अंशदाता द्वारा उसकी बहाली की अवधि के लिए उसे स्वीकृत परिलक्षियों को या उसके एक भाग को बकाए के रूप में भुगतान करने के विकल्प को इस विनियम के प्रयोजनार्थ ड्यूटी पर रहते वक्त परिलक्षियों के रूप में माना जाएगा ।

10. अंशदान की वसूली:

॥१॥ देय अंशदानों को स्थापना वेतन बिल से मातिक रूप में काटे जाएंगे तथा इनको निधि लेखे में जमा के तहत समायोजित किया जाएगा ।

बश्यते कि सरकार द्वारा निर्गमित स्वायत या नियन्त्रित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए अंशदाता के मामले में ऐसे निकाय द्वारा अंशदान वसूल करके लेखा अधिकारी को अग्रेष्टि किया जाएगा ।

॥२॥ ऐसी जमा/गई राशि को हर माह के समाप्त होते ही स्थापना वेतन बिल से भविष्य निधि खाते में, रखा जाएगा, जिसे लेखा अधिकारी अपने पात रखेगा ।

11. अंशदान की गतिः :

इस विनियम 8क के तहत बोर्ड का अंशदान परिलक्षित्यों का 8 1/3 % होगा 1.4.93 से 10 % जिस पर अंशदाता ने अंशदान किया हो तथा उसे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले या विनियम 24 के तहत लेखा जब समाप्त हो उसके बाते में जमा कर दिया जाएगा ।

बगती कि अगर वर्ष के दौरान अंशदाता सेवा छोड़ जाता है या मर जाता है तो पूर्वगामी वर्ष की अन्तिम तारीख तथा आकृत्मिकता की तारीख के बीच की अवधि के लिए अंशदान को उसके बाते में जमा कर दिया जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि विनियम के तहत अंशदाता को अंशदान न करने की अनुमति या निधि को अंशदान न करने की अवधि के सम्बन्ध में कोई अंशदान देय नहीं होगा ।

इसी छुट्टी के दौरान अंशदाता अगर अंशदान देना चाहता है तो इस विनियम के प्रयोजनार्थ उसकी छुट्टी के वेतन को डियूटी पर रहते वक्त उसके द्वारा ली गई परिलक्षित्यों के समान माना जाएगा ।

इसी निलम्बन की अवधि के दौरान अगर अंशदान अंशदान के बिना का भुगतान करना चाहता है तो उस बहाली की अवधि के लिए स्वीकृत परिलक्षित्यों या उसके भाग को इस विनियम के प्रयोजनार्थ डियूटी पर रहते वक्त उसके द्वारा ली गई परिलक्षित्यों के समान माना जाएगा ।

इसी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर रहते वक्त की अविधि के सम्बन्ध में देय राशि अगर विदेशी नियोक्ता से वसूल न की गयी हो तो बोर्ड अंशदाता से वसूल करेगा ।

इस देय अंशदान की राशि को अगले पूर्णक में किया जाएगा ।

12. विशेष अंगदानः

॥१॥ निपि को बोर्ड के अंगदान के अतिरिक्त विनियम ॥१॥ के तहत ऐसे अंगदाता, जिनकी सेवा मंजूरी प्राप्तिकारी द्वारा अप्ती, दक्ष, विश्वासपात्र तथा लगातार प्रभाषिक की जाती है तो उसके बाते में विशेष अंगदान की राशि जमा कर दी जाएगी ।

॥२॥ विशेष अंगदान के भुगतान के लिए गतें :

॥१॥ वर्ग-१ तथा २ के अधिकारियों के लिए:

१. १५ वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ५८ वर्ष की आय पर पहुँचने पर, या
२. ३० वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, या
३. ५० वर्ष की आयु के बाद लेकिन ३५ वर्ष की आय से पहले बोर्ड की सेवा में प्रवेश करने पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ॥सेवानिवृत्ति॥ विनियम के विनियम ५ के तहत अतिवार्य सेवा निवृत्ति पर, या
४. ५० वर्ष की आयु के बाद लेकिन ३५ वर्ष की आयु से पहले बोर्ड की सेवा में प्रवेश करने पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ॥सेवानिवृत्ति॥ विनियम के विनियम ६ के तहत स्पैचिंड सेवानिवृत्ति पर या बनायी गई तथा लागू की गयी कोई अन्य स्पैचिंड सेवानिवृत्ति योजना पर, या
५. शारीरिक या मानसिक अशक्तता की वजह से स्थाई अस्थक्षमता के रूप में प्रभाषिक करने पर, या
६. उसकी मृत्यु पर, या
७. स्थापना में छटौती करने पर बोर्ड की सेवा के लिए उसके लिए कोई अन्य योग्य रोजगार न रहने पर ।

टिप्पणी: वर्ग-१ व २ की सेवाओं के कर्मचारियों के मालिनी में उन्हें सेवा से छुट्कास्त करने पर विशेष अंगदान ग्राहक नहीं होगा ।

बी० अन्य अंगदाताओं के लिए :

जब अंगदाता तेवा को छोड़ देता है तो

1. 15 वर्ष या उससे ज्यादा तेवा के बाद 58 वर्ष की अवयु पर, या
2. 55 वर्ष की आयु के बाद तथा 15 वर्ष की तेवा समाप्त करने के बाद मद्रास पोर्ट इन्स्टर्ट कर्मचारी तेवानिवृत्ति विनियम के तहत अनिवार्य/स्वैच्छिक तेवानिवृत्ति या बनायी गई तथा लागू की गयी कोई अन्य स्वैच्छिक तेवानिवृत्ति योजना, या
3. 10 वर्ष की तेवा पूरा करने से पहले इस्तीफा देने या द्वराचार के तिवाय अन्य क्षणों से तेवा से निकालने या तेवा मुक्त करने, या
4. तेवा से बरखास्त करने पर अंगदाता 15 वर्ष से ज्यादा तेवा पूरी करने पर ही विशेष अंगदान के लिए टकदार होगा ।

नोट:

10 वर्ष की तेवा पूरी करने के बाद ऐसे मामले तथा तेवा से त्याग पत्र दे देने वाले मामलों में अगर कर्मचारी के द्वराचार से बोर्ड को कोई वित्तीय नुकसान पहुँचा है तो कर्मचारी द्वारा किए गये नुकसान के बराबर की राशि को उसको मुग्हान की जाने वाली विशेष अंगदान की राशि से काट लिया जाएगा ।

5. शारीरिक अशक्तता से स्थाई अक्षमता के रूप में प्रमाणित करने पर, या
6. स्थापना को काम करने की वजह से उसके पद को समाप्त करने पर बोर्ड की तेवा में उसके लिए कोई अन्य योग्य पद न रहने पर, या
7. उसकी मृत्यु पर

॥१॥ सामान्यतया दुराधार की वजह से तेवा मुक्ति किए गए अंशदाता के भविष्य निपि खाते में विशेष अंशदान को जमा नहीं दिया जाएगा । विशेष मामले में दुराधार का विशेष कार्य तेवा मुक्ति के लिए अधिक गंभीर हो तो अगर अंशदाता की पूर्व तेवा लम्बी तथा लगातार अच्छी, दक्ष, विश्वासपाल है तो, स्वीकृ तिदाता अपने विवेकानुसार विशेष अंशदान को पूरा या एक हिस्से को उस अंशदाता के भविष्य निपि खाते में जमा करने का आदेश दे सकता है ।

॥२॥ विशेष अंशदान प्रदात छरने वाले मामलों की जारी के लिए कर्मधारी द्वारा की गई तेवा का स्तर अच्छा, दक्ष, विश्वासपाल होना ही तिर्फ औपचारिक नहीं माना जाएगा । अगर किसी मामले में, कर्मधारी की तेवा रिकार्ड की समीक्षा से यह पता चलता है कि उसकी पूरी तेवा अपेक्षित स्तर पर नहीं रही है तो यह विचार किया जाएगा कि साधारण रूप से स्वीकार्य विशेष अंशदान को पूर्ण रूप से या छाट कर या पूरा रद्द करके जमा किया जाए ।

॥३॥ सामान्यतः गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने से विशेष अंशदान के लिए गैर कानूनी हड़ताल से पहले की गई तेवा की हकदारी समाप्त हो जाती है । विशेष मामलों में अध्यक्ष के आदेश से इस विनियम में छूट दी जा सकती है तथा वे यह निर्णय लेंगे कि विशेष अंशदान की राशि की गणना हेतु अंशदाता द्वारा की गई तेवा से, किस अवधि को अगर कोई है तो घटाया जाए ।

३. विशेष अंशदान की राशि :

॥१॥ वर्ग-। तथा 2 के अंशदाताओं के मामले में विशेष अंशदान की राशि हर पूरी की हुई तेवा की अवधि छह माह की अवधि के लिए एक चौथाई माह की परिलिंग्धियों के बाराबर होगी बश्यत कि अधिकतम 16 1/2 माह की परिलिंग्धियों या रूपरेखा लाख जो भी कम हो वह लेकिन अगर किसी भी अंशदाता की मृत्यु 5 वर्ष की तेवा छरने के बाद हो जाती है तो उसके मामले में विशेष अंशदान जो 12 माह की परिलिंग्धियों से कम न हो दिया जाएगा ।

॥२॥ वर्ग-३ तथा ४ के अंगदाताओं के मामले में विशेष अंगदान की राशि हर पूरी की हुई सेवा की छह माह की अवधि के लिए एक चौथाई माह की परिलक्षियों के बराबर होगी जो कि अधिकातम १५ माह की परिलक्षियों होगी, लेकिन किसी भी अंगदाता की मृत्यु ५ वर्ष की सेवा करने के बाद हो जाती है तो उसके मामले में, विशेष अंगदान जो १२ माह की परिलक्षियों से कम न हो दिया जाएगा ।

५. अर्हक सेवा के लिए जोड़

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी **॥सेवानिवृत्ति॥** विनियम के विनियम ७ के तहत स्वैच्छक सेवा निवृत्ति कर्मचारी की भविष्य निधि में आनुपातिक विशेष अंगदान प्रदान करते समय उसके द्वारा की गई वास्तविक योग्य अर्हक सेवा में ५ वर्ष तक वरीयता जोड़ी जाएगी । ५ वर्ष तक वरीयता निम्न लिखित गतों पर दी जाएगी ।

॥३॥ वर्ग-१ तथा २ के कर्मचारियों के मामले में जो अंगदारी भविष्य निधि के तहत आते हैं और इसके तहत रहने का विकल्प दिया है तो वरीयता देने के बाद कुल अर्हक सेवा किसी भी हालत में ३३ वर्ष से ज्यादा न हो तथा वह अधिवर्षिता की तारीख के आगे न बढ़ जाए ।

॥४॥ वर्ग-३ तथा ४ के कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से अंगदारी भविष्य निधि योजना के तहत पोर्ट के वेतन की उदारीकृत परिभाषा के तहत आते हैं, तथा वर्ग-३ तथा ४ के कर्मचारी जिन्होंने पेंशन योजना तथा पोर्ट वेतन की उदारीकृत परिभाषा के लिए विकल्प दिया है के मामले में वरीयता स्वीकार्य नहीं है ।

॥५॥ भविष्य निधि के विशेष अंगदान के प्रयोजनार्थ वरीयता तिर्फ अर्हक सेवा में जोड़ी जाएगी तथा भविष्य निधि को बोर्ड के साधारण अंगदान में नहीं ।

॥३॥ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि को विशेष अंशदान प्रदान करना मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि विनियम में निर्धारित अन्य गतों के तहत होगा ।

॥४॥ भविष्य निधि को विशेष अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ कोई कार्यपालिक वेतन निर्धारित करने पर उपरोक्त वरीयता प्रदान करने में अधिकारी पात्र नहीं होगा ।

॥५॥ जन हित में बोर्ड द्वारा स्थाई रूप से सेवा निवृत्ति करने वालों के मामलों में इस विनियम में सन्दर्भित उपरोक्त ५ वर्ष की वरीयता स्वीकार्य नहीं होंगी ।

॥६॥ अगर कर्मचारी स्वायत निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र राज्य सरकार आदि में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद, वहाँ विलय के लिए सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और वे जाने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए इच्छुक हैं, तो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ उन्हें लागू नहीं होंगे ।

त्रौदः:

॥१॥ इस विनियम के प्रयोजनार्थ छह माह की पूरी की दृष्टि सेवा की गणना में अस्वीकृत छुट्टी की अवधि या सेवा निवृत्ति की तैयारी के लिए कोई छुट्टी जो उन्हें ५८ वर्ष की आयु के बाद सेवा नियम के अनुसार स्वीकार्य है या ५८ वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ाई गई उसकी सेवा की अवधि आदि शामिल नहीं की जाएगी ।

॥२॥ जब किसी भी कर्मचारी को घटार हुए वेतन पर सेवा में रखा जाता है तथा वेतन में घटोतरी उसकी गतती की क्षण से न होकर अन्य कारणों से हो या उसकी अधिवर्क्षिता की तारीख के बाद घटार हुए वेतन पर उसे सेवा में रखा गया है या सेवा मुक्ति के बाद उसे पुनः नियुक्ति किया गया या सेवानिवृत्ति तथा सेवा में रुकावट यदि कोई है तो, उसे माफ किया गया, तो इस विनियम के तहत विशेष अंशदान की गणना के लिए हर सेवा की अवधि

की समाप्ति पर उसके द्वारा सम्बंधित अवधि में प्राप्त वास्तविक वेतन की दर, अगर वह उसके लिए अनुकूल हो, पर ही स्वीकार्य होगी । इस प्रयोजनार्थ कर्मचारी की कुल सेवा की गणना के लिए वर्ग-1 तथा 2 के अधिकारियों के सम्बंध में अधिकतम सीमा 33 वर्ष तथा वर्ग-3 तथा 4 के कर्मचारियों के सम्बंध में 30 वर्ष होगी ।

उच्च श्रेणी में स्कावट की अवधि की सेवा, अगर कर्मचारी के लिए निम्न श्रेणी में अधिक लाभदायक है तो विशेष अंशदान के लिए स्वीकार की जाएगी ।

5. अतिरिक्त राशि :

अंशदाता जो, अधिनियम की धारा 25 ॥1॥ ॥१॥ के तहत सन्दर्भित के अलावा दूसरा पद धारी हो तथा जिसे इयूटी के दौरान घायल होने से आगे सेवा के लिए अक्षम घोषित कर दिया जाता है या इयूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अध्यक्ष भविष्य निधि में विशेष अंशदान जमा करने के अतिरिक्त प्रत्येक मासमें मूल्य 2,500/- की राशि उसको भुगतान करेंगे या अगर उसकी मृत्यु हो गई हो मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित या आश्रितों जिनका प्रत्येक मासमें निर्णय लिया गया है को भुगतान दिया जाएगा ।

6. छ्याज़ :

इस विनियम के उप-विनियम ॥1॥ तथा ॥५॥ के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि पर छ्याज नहीं लगाया जाएगा ।

13. उपदान अधिनियम 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए उपदान का भुगतान तथा उसके तहत समय समय पर बनास गए नियमः-

कर्मचारी जिन्हें उपदान अधिनियम 1972 के तहत भुगतान लागू होता है, वे समय समय पर यथा संशोधित उपदान अधिनियम का भुगतान 1972 का अधिनियम 30 दिसंबर के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके तहत समय समय पर बनाए गए नियम बत्ते कि उदारीकरण का अनुपालन किया हो या विनियम 12 दिसंबर के तहत विशेष अंशदान जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के अनुसार उपदान के लिए पात्र होगे ।

नोट: उपदान की गणना को प्रयोजनार्थ वेतन में सभी परिलक्षियाँ अर्थात् एफ आर 9 दिसंबर के तहत परिभाषित वेतन, परिवर्तनशील महेंगाई भत्ता सहित महेंगाई भत्ता, पीस रेट उपार्जन तथा जहरों कहीं लागू हो योजना के परिपाय स्वरूप भुगतान के तहत अन्य ऐसे भुगतान या बोर्ड द्वारा बनाए गए अन्य किसी विनियम में परिभाषित किसी ऐसी परिलक्षियों को शामिल किया जाएगा ।

लेकिन पीस रेट प्रोत्साहन द्वारा अनुशासित तथा परिपायी योजना द्वारा भुगतान वाले वर्ग के सम्बन्ध में वेतन की गणना उसके रोजगार को समाप्त करने के तुरन्त पहले के तीन माह की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त भुगतान के कुल वेतन के औसत पर ही की जाएगी ।

उपदान के भुगतान का विवरण, नामांकन को भरने की रीति, उपदान की स्वीकार्यता, आदि का निपरिष उपदान अधिनियम 1972 का भुगतान तथा उसके तहत बनाए गए नियम तथा समय समय पर संशोधन, आदि के तहत ही होगा ।

14. निवेश :

===== निधि के प्रयोजनार्थ तुरन्त न आवश्यक राशि का समय समय पर बोर्ड द्वारा निवेश किया जाएगा तथा बोर्ड के नाम पर भारतीय द्रुस्ट अधिनियम 1882 द्वारा प्राधिकृत बंध पत्र में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में या राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थायी जमा में या समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे निवेशों में रखा जाएगा तथा निधि के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो तो समय समय पर अपने नाम पर रहने वाले प्रत्याभूतियों को छेकर या स्थायी निषेप की वापरी पर राशि या राशियों को आर्जत करेगा ।

15. उत्तरोत्तर व्याजः

इस दिनांक 1.4.1963 से अंशदाता द्वारा किए गए सभी अंशदानों, जिसमें अगर ऐसी किसी राशि का भुगतान वर्ष के दौरान विनियम 16 के तहत बीमा पॉलिसी या पॉलिव्हिधियों के प्रति किया गया है, भी शामिल होगा तथा विनियम 14 के तहत भविष्य निधि निवेश पर पिछले वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अर्जित, प्रति वर्ष की व्याज की दर सहित विनियम 11 के तहत स्वीकार्य बोर्ड का अंशदान इकिसी भी विशेष अंशदान को छोड़कर, जिस पर वात्तविक व्याज भी लगाया जाएगा, सहित अंशदाता के खाते में डाला जाएगा, पर व्याज दिया जाएगा ।

नोट : इस विनियम के प्रयोजनार्थ व्याज की दर को अगले 1/4 प्रतिशत में पूर्णरूपित किया जाएगा ।

इसी व्याज की गणना निम्न लिखित प्रकार से की जाएगी लेके को समाप्त करते वर्षत एक वर्ष के लिए या कोई लघु अवधि के लिए आवश्यक हरेक अंशदाता के कुल ऐसों को छोड़कर, न्यूनतम मासिक शेष को निश्चित किया जाएगा तथा ऐसे कुल पर उपयुक्त दर या दरों पर एक वर्ष या कोई विनियोजित लघु अवधि के लिए एक माह का व्याज लगाया जाएगा ।

इसी ४ इन प्रकार पारिकालित किए गये व्याज को हर वर्ष की समाप्ति पर मूलधन के साथ या अगर वर्ष के दौरान समाप्त करते हों तो खाते को समाप्त करने पर जोड़ा जाएगा ।

इडी४ ऐसा अंशदाता जो मर जाता है या सेवा छोड़ देता है या वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त होता है के मामले में भुगतान करने वाले महीने के पूर्व गामी महीने में या ऐसी राशि भुगतान के लिए देय हो, के बाद के छह माह के समाप्त वाले माह, इनमें से जो अवधि कम है, में पिछले वित्तीय माह के लिए निर्धारित उपयुक्त दर पर व्याज का भुगतान किया जाएगा ।

बास्ते कि उन मामलों में जिन में लेखा अधिकारी वैयक्तिक रूप से संतुष्ट हो कि भुगतान में देरी की बजह अंशदाता के नियन्त्रणाधीन परिस्थितियों से परे हो तथा कि उस मामले के प्रशासनिक विलम्ब की पूर्ण जाँच करके कार्रवाई ली गई है, तो जिस माह में राशि का भुगतान हो उसके बाद एक वर्ष तक का व्याज दिया जाएगा ।

नोट: ऐसा अंशदाता जिसकी मृत्यु हो जाती है तथा नामिती के नाबालिंग होने से उसके खाते की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो इस विनियम के तहत राशि के भुगतान तक या अंशदाता की मृत्यु के बाद छह माह तक जो भी पहले हो अंशदाता की राशि में व्याज जोड़ा जाएगा ।

16. बीमा पालिसी के प्रति भुगतान:

अंशदाता तथा बोर्ड के बीच पारास्परिक सहमति से बीमा पालिसी के प्रति भुगतान सिर्फ उन्हीं अंशदाताओं पर लागू होगा जिन्होंने १. ८. १९६९ से पहले जीवन बीमा पालिसी के लिए निधि से वापसी के लिए अनुमति प्राप्त करली हो तथा यह सुविधा १. ८. १९६९ के बाद बाली किसी पालिसी के लिए नहीं बदाई जाएगी ।

17. प्रोत्ताहन बोनस :

ऐसा अंशदाता जिसने भविष्य निधि लेखे से 1. 4. 78 तथा 1. 4. 79 तथा उसके बाद हर वर्ष । अप्रैल से लगातार 5 वर्ष या 3 वर्ष के दौरान कोई वापसी नहीं ली हो तो, उस मामले में वह 31. 3. 78 तथा 31. 3. 79 तथा पूर्वगामी वर्ष की दिनांक 31 मार्च को तथा उसके पश्चात उसके खाते में जमा समस्त शेष पर राशि पर । ५ की दर से बोनस का हकदार होगा ।

नोट्स:

॥1॥ 1978-79 के दौरान बोनस दर के भूगतान हेतु 5 वर्ष की अवधि 1. 4. 74 से 31. 3. 79 तक तथा उसी प्रकार की अवधि के रूप में होगी ।

ग्रेर वापसी

॥2॥ 1. 4. 1979 से की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है ।

॥3॥ शब्द "वापसी" से तात्पर्य पृति देय तथा अप्रतिदेय वापसी दोनों से है । बीमा पॉलिसी के लिए वापसी से अंशदाता इस सुविधा के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा ।

॥4॥ इस प्रकार परिकलित किए गये बोनस को नजदी की रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा ॥पचास पैसे को अगले रूपस में माना जाएगा॥ भविष्य निधि शेष पर च्याज के अतिरिक्त इसे भी अंशदाता के लेखे में जमा किया जाएगा ।

॥5॥ शेष से तात्पर्य तिर्क अंशदाता के हिस्ते से है तथा उसे ५ माना जाएगा ।

॥6॥ लघु अवधि के लिए अंशदाता के अस्थाई निलम्बन अर्थात् छूटटी पर रहते वक्त या निलम्बनाधीन, इन मामलों में जहाँ भी नियम लगा है को छोड़कर पाँच वर्ष / 3 वर्ष के दौरान अंशदाता द्वारा किए गये अंशदान की निधि पर ही बोनस स्वीकार्य होगा ।

॥7॥ बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है । अगर कोई अंशदाता वर्ष के मध्य निधि में शामिल होता है, या सेवा को छोड़ देता है तो शामिल होने का वर्ष तथा सेवा को छोड़ देने के वर्ष को पूरे वर्ष के रूप में माना जाएगा ।

18. अन्य सेवा से/को स्थानान्तरण :

कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में आता है, और अगर वह निधि का अंशदाता बनता है तो किसी तरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में आने की तारीख तक वहाँ की भविष्य निधि के खाते में उसकी जमा राशि को स्थानान्तरित किया जाएगा बशर्ते कि हरेक मामले में बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। इस प्रकार स्थानान्तरित राशि पर किंई व्याज ही लगाया जाएगा, इस पर बोर्ड द्वारा अंशदान के लिए अंशदाता को कोई हक नहीं होगा।

अगर किसी अंशदाता की सेवा स्थाई रूप से किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा में स्थानान्तरित की जाती है तो उसके भविष्य निधि लेखे के शेष को उसे नकद भुगतान करने के बजाय नियोक्ता के पास उसके खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा।

19. निधि से अग्रिम :

अध्यक्ष के विवेकानुलार अंशदाता की निधि के खाते में व्याज सहित राशि **जिसमें बोर्ड का अंशदान, उस पर व्याज शामिल नहीं है** से अस्थाई अंग्रेम अंशदाता को दिया जाएगा जो निम्न लिखित शर्तों से विद्युत होगा।

॥१॥ निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों हेतु अग्रिम का भुगतान:

- बीमारी :** अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उस पर निर्भर व्यक्ति की बीमारी या पारिवारिक या अशक्तता के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान।
- वाध्यकर व्यय:** अंशदाता की प्रतिष्ठा के अनुगार वाध्यकर व्यय, जो सामाजिक रीति रिवाज जैसे कि सगाई/गादी, अंतिम संस्कार, पर्मानुष्ठान आदि के लिए अंशदाता के पास्तविक आवश्यकता व्यक्तियों के लिए उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया हो।

३. **शिक्षा:** निम्न लिखित मामलों में अंशदाता तथा उसके पारंपार के सदस्य या उस पर पात्ताधिक रूप से आश्वित व्यक्ति की उच्च शिक्षा हेतु उत्पन्न व्यय के लिए उच्च विद्यालय के स्तर के बाद

११४ उच्च विद्यालय के स्तर के बाद शैक्षिक, तकनीकी, प्राध्यापकी या व्यावसायिक, पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी में शिक्षा प्राप्त करने हेतु । तथा ११५ भारत में उच्च विद्यालय के स्तर के बाद विकितसा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विनिर्दिष्टित पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु बशर्ते कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो ।

४. **कानूनी :** निम्न लिखित मामलों में अंशदाता द्वारा कानूनी व्यय को पूरा करने हेतु :-

११६ उसके द्वारा किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप के लिए या दूषटी को निभाते वक्त उसके द्वारा ऐसे किसी कार्य के लिए लगाये गये आरोप के अभिप्राय के विरुद्ध उसे निर्दोष साबित करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आवश्य लेने वाले मामले में, या

११७ किसी कार्यालयी द्वारावारी आरोप के लिए उस पर अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया जाता है, या अंशदाता अपने बचाव के लिए जाँच हेतु कानूनी पेशाशार की मदद लेता है तो ऐसे मामले में, या लेकिन निम्न लिखित के लिए कोई अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा :-

११८ कोई ऐसी घटना जिसमें बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति न हो, और वह कर्मचारी कोर्ट का आवश्य लेता है तो उस मामले में ।

॥२॥ जब कोई कर्मयारी अपनी सेवा के मामले में कोई शिकायत करता है या उस पर लगास गए किसी दण्ड के विरुद्ध बोर्ड के खिलाफ मुकद्दमा लगाता है तो

५. पुनःनिर्माण :

तुफान, बाढ़, आग आदि की घजह से क्षतिग्रस्त अपनी बोर्डी या घर को पुनः बनाने के प्रति लघ्य को पूरा करने ।

६. न विनिर्दिष्ट किए गये किसी भी प्रयोजन हेतु :

विशेष परिस्थिति में संबंधित अंशदाता जो हन विनियम में न विनिर्दिष्ट कारण या और संकट में होने से अग्रिम की माँग करता है और अगर स्वीकृतिदाता तन्तुष्ट है तो स्वीकृति दे सकता है ।

॥२॥ अग्रिम के भुगतान हेतु शर्तेः

- विशेष कारण के सिवाय अन्य कारणों के लिए अग्रिम ३ माह के बेतन से ज्यादा न होगा या अंशदाता की निधि के खाते में जमा शेष राशि, जो भी कम हो वही होगा ।

त्रोटः

इस विनियम में बेतन से तात्पर्य विनियम ३ ॥१॥ ॥७॥ के तहत परिभाषित परिलक्षियों से है ।

- विशेष कारणों को छोड़कर पिछले सब अग्रिमों की अन्तिम वापरीसे कम से कम १२ महीने के बाद ही अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी ।
- अगर अग्रिम पिछले अग्रिम की अन्तिम वापरी के समाप्त होने से पहले स्वीकृत किया जाता है तो, पिछले आग्रिम की शेष वापरी को ऐसे स्वीकृत अग्रिम में जोड़ा जाएगा तथा वापरी के लिए किश्त समेकित राशि पर ही निर्धारित की जाएगी ।

20. अग्रिमे की वापसी :

इसमें अंशदाता से वसूल किस जाने वाले अग्रिम की संख्या ऐसी बराबर मासिक किश्तों में होनी चाहिए, जैसा स्वीकृतिदाता निर्देश करें, लेकिन ऐसी संख्या 12 से कम न हो, जब तक कि अंशदाता चयन न करें, या किसी भी मामले में 36 से ज्यादा न हो। कोई भी अंशदाता अपने विकल्प पर उपरोक्त विनिर्दिष्ट के बजाय छोटी किश्त में वापसी कर सकता है। हरेक किश्त पूर्ण रूपरूप में होगी। ऐसी किश्तों के निर्धारण के लिए अग्रिम की राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

बी) अंशदानों के लिए वसूली विनियम 10 के तहत बताए गए तरीके से की जाएगी तथा यह अग्रिम देने के बाद छुट्टी वेतन या निर्वाहि अनुदान को छोड़कर ^{अंशदाता} प्राप्त भुगतान वालीपहली परिलाभिधयों से की जाएगी। छुट्टी पर रहते वक्त या निर्वाहि अनुदान पर रहते वक्त अंशदाता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी तथा अंशदाता को स्वीकृत वेतन से अग्रिम की वसूली को स्वीकृतिदाता द्वारा मूल्तची किया जा सकता है।

सन्देश) अगर अंशदाता द्वारा एक से ज्यादा अग्रिम लिया गया है तो वसूली के प्रयोजन हेतु हरेक को अलग माना जाएगा।

21. अग्रिम का गलत उपयोग:

इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी अगर स्वीकृतिदाता इस बात से तनाव लेता है कि विनियम 19 के तहत निधि से जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया गया है का प्रयोजन उसी प्रयोजन हेतु नहीं किया गया है तो अंशदाता को उस अग्रिम की राशि को निधि को वापस करना होगा या अगर ऐसा न करने से स्वीकृतिदाता यह आदेश दे सकता है कि अगर अंशदाता छुट्टी पर हो तो भी उसकी पारलाभिधयों से एक या ज्यादा मासिक किश्तों में जो 12 से ज्यादा न हो, जिसका निर्धारण स्वीकृतिदाता जरेगा, से वसूल किया जाए।

नोट : इन विनियम में बताए गए शब्द परिलाभिधयों में निर्वाहि अनुदान शामिल नहीं है।

22. अंगिम पर व्याजः

=====

अंशदाता को दिए गये अंगिम की कोई भी राशि जो उसके खाते से आउटस्टेटिंग अंगिम के रूप में कुछ समय के लिए नामे डाला गया है, पर कोई व्याज नहीं लगाया जाएगा ।

23. निधि से अन्तिम निकासी :

=====

१। अंशदाता स्वीकृतिदाता की स्वीकृति से उसके अंशदान की राशि तथा उस पर जो उसके भविष्य निधि लेखे में है लगे व्याज

से अन्तिम वापसी ले सकता है, बश्ते कि उसमें बताई गई शर्तों से विपर्य हो ।

२. भावासु : अंशदाता की सेवा के दौरान एक या उससे ज्यादा प्रयोजन हेतु, अर्थात्,

३. शू उस रहने के लिए उपयुक्त मकान के निर्माण या प्रापण या बना बनाया प्लाट के लिए जिसमें स्टेट हाउसिंग बोर्ड/को आपरेटिव बिल्डिंग टोसाइटीस से अर्जित करने के लिए प्रस्तावत साइट का मूल्य भी शामिल है ।

४. बी३ रहने के लिए बनाने या उपयुक्त मकान या बना बनाया प्लाट के प्रापण हेतु लिए गए ऋण की शेष राशि की वापसी हेतु :

बश्ते कि अंशदाता के खाते में उसके द्वारा किए गये वास्तविक अंशदानों तथा उस पर लगा व्याज सहित वास्तविक राशि या मकान/प्लाट जिसमें साइट मूल्य भी शामिल है, का वास्तविक मूल्य, के लिए, लिए गये ऋण की वापसी अगर है तो वह जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।

५. सी३ रहने के लिए मकान बनाने हेतु दाउस साइट की खरीदारी या इस प्रयोजन हेतु लिए गये किसी ऋण की वापसी हेतु ।

बश्ते कि उपरोक्त बताए गए आवेदन की तारीख से 12 महीने के पहले कोई ऋण न लिया गया हो ।

यह भी प्रावधान है कि निकासी करने वाली राशि अंशदाता के खाते में उसके द्वारा इकती किए गए अंशदान तथा उस पर लगी व्याज सहित राशि की आपी राशि से ज्यादा न हो या साइट वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो वह

स्पष्टीकरणः

बिक्री स्थानान्तरण तथा निष्पादन विलेख के सम्बन्ध में उत्पन्न वास्तविक व्यय को साइट मूल्य के एक फ्रैट के रूप में गिना जाएगा ।

११) खंड १२) के तहत खरीदे गये स्थान पर मकान का निर्माण:-

बशर्ते कि प्रयोजन हेतु निकासी की राशि, व्याज सहित वास्तविक अंशदान की राशि, जो उसके खाते में है से ज्यादा न हो या मकान के निर्माण में लगा वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो वह

१३) निधि या अन्य सरकारी स्रोतों की मदद के बिना मालिक होने या अर्जित मकान या प्लाट के परिवर्तन या परिवर्धन हेतु ।

बशर्ते कि निकासी की राशि, व्याज सहित वास्तविक अंशदान की राशि से ज्यादा न हो या रूपर 10,000/- जो भी कम हो, वह ।

टिप्पणी :

इन विनियमों के तहत निकासियों की मंजूरी करते समय मंजूरी प्राप्तिकारी को स्वयं निम्न लिखित बातों पर संतुष्ट होना चाहिए कि मकान प्लैट/स्थान का आकार और मूल्य असंगत नहीं है:-

- १) सम्बंधित अंशदाता की प्रतिष्ठा और
- २) उसके/की भविष्य निधि लेखे में उपलब्ध स्रोत ।
- ३) वात्तव में राशि, मकान/प्लैट/साइट खरीदने के प्रयोजन के लिए या उपरोक्त के लिए लिए गये ग्रण की वापसी के लिए जैसा भी मामला हो, अपेक्षित है और
- ४) खरीदे जाने वाले प्रत्तार्गित मकान/प्लाट/साइट का पूरा टाइटल अंशदाता प्राप्त करेगा ।

2. खण्ड [ए] के उप खण्ड [ए] या [ई] के तहत निकासी के लिए अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जहाँ मकान साईट या मकान पट्टानी या पत्ति के नाम पर हो वशर्ते कि वह अंशदाता द्वारा दिये गए नामांकन में भविष्य निधि रकम को प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिनी के रूप में हो ।

3. खण्ड [ए] का उप खण्ड [ए], [डी] या [ई] के तहत निकासी की मंजूरी केवल तभी की जाएगी जब कि अंशदाता निर्मित करने वाले मकान का प्लान या उसमें परिवर्तन और परिवर्धन लाना हो तो उस प्लान को प्रस्तुत करेगा वशर्ते कि जहाँ साईट या मकान हो उस मकान का प्लान स्थानीय नगर-पालिका द्वारा अनुमोदित करा लेना चाहिए और केवल प्लान के वास्तविक अनुमोदन लेने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी ।

4. उप खण्ड [ए] या [डी] के तहत मकान/प्लैट के निर्माण के मामलों में निकासी केवल बराबर कित्तों में ही स्वीकारी जाएगी । [दो से कम नहीं और चार से ज्यादा नहीं], प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त की मंजूरी मकान/प्लैट के निर्माण की प्रगति के आधार पर ही प्राप्तिकर्ता द्वारा दी जाएगी ।

5. रकम के निकालने के छः महीनों के भीतर मकान का निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए और निर्माण कार्य की शुरुआत की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर समाप्त कर देना चाहिए ।

मंजूरी प्राप्तिकारी अपने स्वयंप्रेक्ष से निर्धारित छः महीने की अवधि को स्क साल तक बढ़ा सकता है ।

6. उप खण्ड [बी] के तहत मकान/प्लैट को खरीदने या गिरवी से छुड़ाने के प्रयोगन के लिए, लिए गए श्रण की वापसी के लिए पूर्ण तय या अंशतः राशि निकाली जाए तो वह श्रण निकासी के दिन से तीन माह के भीतर परिसमाप्त कर देना चाहिए ।

7. अगर मकान साईट एक मुश्त खरीद पर की जाती है या इस प्रयोजन के लिए पहले ही लिए गए शृण की वापसी के लिए हो तो निकासी एक ही किस्त में दिया जा सकता है और साईट किस्त पर खरीदे तो किस्तें तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

8. निकासी या निकासी की प्रथम किस्त जैसा भी नामला हो एक महीने की अवधि के भीतर हाउस साईट खरीद लेनी चाहिए । इस शर्त को पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राप्तिर्त को प्रत्युत करना अपेक्षित है । तथा निकासी/किस्त की राशि को सम्पूर्णतया या साईट की खरीद के लिए भुगतान करके उपयोग में लाया गया इसे साझित करने के लिए विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राप्तिर्त को प्रत्युत करना अपेक्षित है ।

9. भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए कार्य आवास और आपूर्ति मंत्रालय की योजना के तहत या इस मामले में अन्य किसी सरकार से या पोर्ट ट्रस्ट से सहायता पाने के लिए स्वीकारा गया है के तहत अंशदाता जिसले स्वयं अग्रिम प्राप्त उक्त हो तो अपर चर्चित प्रयोजनों के लिए इन विनियमों के तहत अंतिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र होगा ।

परन्तु उपरोक्त योजना के तहत या अन्य सरकारी स्रोतों या पोर्ट ट्रस्ट स्रोतों के तहत निकाले गए अग्रिम के साथ इन विनियमों के तहत निकाली गई राशि दोनों उक्त योजना के तहत समय समय पर निर्धारित अधिकतम रीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

10. अगर मकान/प्लैट/साईट आदि स्टेट हाउसिंग बोर्ड/कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसाईटीज से प्राप्त करना हो तो निकासी, अंशदान तथा व्याज सहित वास्तविक राशि की मंजूरी दी जाएगी, ताकि,

- १। आवंटित मकान/प्लैट के पहले भुगतान के लिए और
- २। हॉसिंग बोर्ड को एक मुश्त भुगतान ताकि कर्मचारी सेवा में रहते समय उसके द्वारा देय किस्तों को कम किया जा सके या शेष देय किस्तों को खत्म किया जा सके ।

11. यह बोर्ड गई निकासी राशि की सहायता से किस गए अंशदानों द्वारा प्रस्तावित मकान/प्लैट साईट को प्राप्त करके या गिरवी से छुड़ायी गयी जगह कर्मचारी के इयूटी स्थान के पास हो या सेवा निवृत्ति के बाद जहाँ वह वास करना चाहता हो ।

12. भवन के प्राप्त करने या मकान या साईट को गिरवी से छुड़ाने के लिए ही निकासी अनुमति होगी ।

बशर्ते कि कर्मचारी अपनी इयूटी के स्थान के पास या सेवा निवृत्ति के बाद आवास करने वाले स्थान के पास या पहले से ही मकान/साईट नहीं रखा हो ।

13. अंशदाता जो उपरोक्त निकासी प्राप्त करता है को एक करार निष्पादित करना होगा और उपरोक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित फार्म और प्रकृति के अनुसार घोषणा करनी होगी ।

14. हाउसिंग के प्रयोजन के लिए इन उप विनियमों के तहत केवल एक ही निकासी के लिए अनुमति होगी ।

15. अंशदाता जब तक बोर्ड की सेवा में रहेगा तब तक प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को या उससे पहले मंजूरी प्राप्तिकारी को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि मकान/प्लैट/साईट का मालिक बही है और उपरोक्त की विभिन्न रूप में मंजूरी प्राप्तिकारी के पूर्व अनुमति के बिना तीन वर्ष या अन्यथा कोई भी अवधि ही के लिए ट्रांफर, बिक्री, भैट, बदलने पट्टे पर देने आदि के जरिस जगह को नहीं बैठा गया हो । अगर अपेक्षित हो तो उसे कर रसीद टाइटल डीड आर्ड को भी प्रस्तुत करना होगा । मंजूरी प्राप्तिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के पहले तीन वर्ष की अवधि से अधिक अगर मकान का विक्रय या भैट या किसी के नाम पर बदलना या गिरवी रखना या पट्टे पर दिया है तो निकासी राशि को विनियम 15 के तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दरों पर प्रोद्भूत व्याज सहित एक किस्त में एक महीने के भीतर वसूल किया जाएगा ।

यूक मामले में मंजूरी प्राप्तिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि अंशदाता उपलब्धियों में से एक मुश्त या मंजूरी प्राप्तिकारी द्वारा निर्णय किए अनुसार मासिक किस्तों में रकम को वसूल किया जाएगा ।

४३ निम्न लिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए अंशदाता द्वारा 20 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद अगर खण्डित अवधि कोई हो तो मिलाकर या उनकी सेवानिवृत्ति की दिनांक के 10 वर्ष पहले के भीतर जो भी पहले हो ।

४४ शिक्षा :

निम्नलिखित मामलों में अंशदाता या उनके किसी बच्ये की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए :-

११ द्वार्ड स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा, भारत से बाहर के लिए अकादामी तकनीकी व्यावसायिक या वैकेसनल कोर्स ।

१२ द्वार्ड स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा भारत के भीतर हो धिकित्ता हंजीनियारिंग या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कोर्स के लिए हो ।

परन्तु यह पात्रकृम तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

यह राशि तीन महीने के देतन की रीमा तक होगी, लेकिन किसी भी कारण से अंशदाता की निधि में जमा राशि और उस पर अर्जित व्याज से अधिक नहीं होगी ।

निकासी प्रति छः माह में एक से अधिक अनुमति नहीं होगी ।

संबंधित अंशदाता, मंजूरी प्राप्तिकारी को, निकासी की दिनांक से छः माह के भीतर यह संषुष्ट करायेगा कि उसने जिस प्रयोजन हेतु यह राशि ली थी उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया है ।

इस विनियम के उप खण्ड ॥1॥ और ॥2॥ उप विनियम ॥2॥ के प्रावधानों में किसी भी बात के होते हूस भी अगर अंशदाता द्वारा निकाली गई राशि का कुछ अंश छः महीने के भीतर खर्च नहीं हुआ हो तो और आगे के छः महीनों की अवधि में अंशदाता पुनः निकालने का प्रस्ताव रखता है तो वह, उपरोक्त छः महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व लिखित रूप में संजूरी प्राधिकारी को बताएगा कि प्रस्तावित निकाली में अधिक राशि को समायोजित कर दिया जाए परन्तु, यह अधिक राशि उपयोग में लाई गई राशि से 10 × से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 और छः महीनों की समाप्ति के पूर्व एक महीने के अन्दर और राशि निकालने की कार्रवाई की जाएगी ।

॥बी॥ सगाई/विवाह :

===== अंशदाता की स्वयं की सगाई/शादी तथा उसके लड़के या लड़कियाँ या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित अन्य कोई महिला/पुरुष रसितेदार का विवाह/सगाई से सम्बन्धित खर्च को पूरा करने के लिए ।

निकाली की राशि हरेक विवाह के मामले में अंशदाता के खाते में जो अंशदान जमा है और उस पर प्रोटभूत व्याज या वर्ग-1 और 2 आधिकारियों के मामले में अपनी आश्रित बेटी/महिला के लिए 10 माह का वेतन या बेटा/पुरुष आश्रित के लिए छः महीनों का वेतन जो भी कम हो और अन्यों के मामले में आश्रित बेटी/पुरुष लिए लिए 10 माह की परिलक्ष्य या आश्रित बेटा/पुरुष के लिए छः माह की परिलक्ष्य जो भी कम हो के बराबर होगी ।

टिप्पणी :

१।१ इस विनियम के प्रयोजन के लिए "विवाह" शब्द में "सगाई" भी शामिल है ।

१।२ "सगाई" और "विवाह" को इस प्रयोजन के लिए अलग अलग माना जाएगा । अंशदाता जो "सगाई" के लिए इस नियम से पैसे निकालता है तो वह "विवाह" के लिए अन्तम निकालीके लिए भी पात्र होगा

३३। अगर लगातार दो या उत्तमे जांधक विवाह कराते हैं तो हरेक विवाह के लिए ग्राह्य राशि का नियरिष इस प्रकार किया जाएगा कि एक की मंजूरी के बाद दूसरी की मंजूरी पृथक पृथक दी गई हो ।

३४। विवाह कराने पे वास्तविक महीने के तीन महीने से पहले निकाती के लिए अनुमति नहीं होगी ।

३५। उसी विवाह के मामले में अंशदाता इन विनियमों की शर्तों पर राशि निकालेगा या विनियम १९ के तहत अस्थाई अंग्रेज लेगा ।

३६। विवाह हो जाने के एक गहीने के भीतर अंशदाता मंजूरी प्राप्तिकर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या अगर वह छुट्टी पर हो तो छुट्टी से लौटाने के बाद एक महीने के भीतर रिपोर्ट करेगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि को निकाला गया था का उसी के लिए वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया है ।

३७। बीमारी :

अंशदाता या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के लम्बी बीमारी के लिए खर्च को पूरा करने हेतु । निकाती वी राशि अंशदाता के खाते में जमा अंशदान और उस पर प्रोद्भूत व्याज या ६ महीनों की परिलिखियाँ जो भी कम हो होगी ।

जिस प्रयोजन के लिए रकम निकाली गयी थी का पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है की रिपोर्ट को निकाती की दिनांक से एक माह के भीतर अंशदाता मंजूरी प्राप्तिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

३८। मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर आदि की खरीद :

अंशदाता १५ वर्ष की सेवा ग्राहक करने के बाद इसमें स्कावट की अधिक कोई हो तो शामल है । या अधिवर्षीयता आय के ५ वर्ष पूर्व मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर की खरीद के लिए यां इस प्रयोजन के लिए अंशदाता द्वारा पहले से ही लिए गए शेयर की वापसी के लिए उसे निकाती की अनुमति दी जा सकती है । वर्तमान कि :-

॥1॥ मोटर कार खरीदने के लिए अंशदाता का मूल वैतन रूपर 3500/- प्रति माह या उससे अधिक होना चाहिए और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामले में रूपर 1500/- प्रति माह या उससे अधिक होना चाहिए ।

॥2॥ मोटर कार की खरीद के लिए रूपर 50,000/- तक और मोटर साइकिल स्कूटर आदि की खरीद के लिए रूपर 8000/- तक निकासी की सीमा है या अंशदाता के खाते में जमा राशि जो भी कम हो ।

॥3॥ ऐसी निकासी केवल एक ही बार अनुमत है ।

॥4॥ दूसरी मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए निकासी के मामले में, हस्त योजना के तहत मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए अर्गिम ग्राह्य नहीं होगा ।

॥5॥ राशि की निकासी के एक माह के भीतर मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर खरीद लेनी चाहिए और खरीद के सबूत को मंजूरी प्राप्तिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो विनियम 15 के तहत सम्पूर्ण राशि को निर्धारित व्याज जैसा कि तय किया गया हो दर के साथ वापस करना होगा ।

॥6॥ मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर का पूर्ण स्वामित्व उसी के नाम पद पर है करके बोर्ड की सेवा में अंशदाता जब तक है प्रति वर्ष मंजूरी प्राप्तिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कार/मोटर साइकिल/स्कूटर को नहीं देयेगा, गिरवी नहीं रखेगा या ट्रांस्फर नहीं करेगा । और अगर वह निकासी की राशि से विमक्त किया गया है तो विवियम 15 के तहत निर्धारित उचित व्याज दर के साथ राशि को वापस करके अंशदाता की भविष्य निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

॥7॥ ऐसा अंशदाता जो उपरोक्त निकासी को प्राप्त करता है वह स्टाम्प पेपर में मंजूरी प्राप्तिकारी को वजन देगा ।

१८५। ९०% निकासी :

अंशदाता सेवा निवृत्ति होने के 12 महीनों के अन्दर बिना किसी प्रयोजन के जोड़े निधि से उसे देय जमा राशि में से ९०% की राशि तक निकालने के लिए अनुमति दी जा सकती है।

अन्तिम निकासी के लिए शर्तें :

१९। पुनः जमा करना :

इस विनियम के तहत निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक बार कोई भी राशि निकाले और वह अंशदाता द्वारा जिस प्रयोजन हेतु लिया गया था। अधिक हो तो उसे निधि में तुरन्त विनियम १५ के तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दारों के ल्याज सहित पुनः जमा कर देना चाहिए।

२०। वापर्ती :

अंशदाता जिसे एक या एक से ज्यादा प्रयोजन हेतु निधि से निकासी लेने की अनुमती दी गयी है, को इस विनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि में स्वीकृतीदाता को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि ली है उसका उसी प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है तथा अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो इस प्रकार निकासी की गई पूर्ण राशि या जिसके लिए आपेक्षन किया था उसे उपयोग में नहीं लाया गया तो उतनी राशि का अंशदाता द्वारा निधि में एक किश्त में वापस करना चाहिए तथा ऐसे न करने पर स्वीकृतीदाता यह आदेश देगा कि अंशदाता की परिलक्षियों में से एक किश्त में या ऐसी किश्तों में, जैसा कि स्वीकृतीदाता उचित समझे, से वसूल की जाएगी।

२१। अन्तिम निकासी के प्रयोजन हेतु प्रपत्र तथा प्रक्रिया :

इस विनियम के तहत बताई गई रीति तथा फार्म, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तथा निर्देशित किया जाएगा, के अनुसार एक या एक से ज्यादा प्रयोजनार्थ निकासी की राशि के लिए अंशदाता को आवश्यक करार, निष्पादन, धोषणा पत्र को प्रत्युत करना, तथा उचित रूप से क्षस्तावेजी प्रमाण प्रत्युत करना चाहिए।

३३ परिवर्तन :

विनियम 19 के तहत किसी प्रयोजनार्थ लिए गये अस्थाई अग्रिम के शेष को अंशदाता के लिखित निवेदन पर इस विनियम के तहत अन्तिम निकासी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी निकासी के समय वह उसमें निर्धारित शर्तों के पूरा करता हो ।

24. लेखे को बन्द करना तथा भुगतान :

सेवा को छोड़कर जाते समय इस विनियम तथा विनियम 25 के तहत कोई क्षटौती है तो अंशदाता के खाते को बंद करके उसके खाते लेखे में रहने वाली राशि से काटकर शेष की अदायगी की जाएगी ।

४४ जब वह बोर्ड की सेवा से पदव्युत या निकाला जाता है या उसके आचार या अक्षमता की वजह से उससे त्याग पत्र देने को कहा जाता है या कोई सूचना दिए बिना उसके त्याग पत्र देने या जब वह परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर भी उसकी पुष्टि नहीं^{की} जाती है, तो,

११ १५ वर्ष की सेवा से पहले गंभीर दुरभार से पदव्युत किया जाता है, या १२ विधि में शामिल होने के ५ वर्ष के अन्तर्गत उसके त्याग पत्र देने या मृत्यु, अधिवर्षिता या ट्रस्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसको आगे की सेवा में रहने से अयोग्य घोषित करने आदि को छोड़कर अन्य कारणों से ट्रस्ट के कर्मचारी के रूप में उसे अधिकार न देने या पद को समाप्त कराने या स्थापना में शटौती करने ।

बोर्ड उसके अंशदान के खाते की शेष राशि को पूरा या उसके अंश को रोक सकता है तथा उसे उसके द्वारा किए गए अंशदान तथा उस पर लगे छाप तहित शेष, अगर है तो, की भुगतान ही किया जाएगा ।

बश्यते कि पदच्यूत त्याग पत्र के आदेश को रद्द करने पर रोकी गई राशि को उसके पुनः सेवा में आते ही उसकी निधि के खाते में डाली जाएगी ।

बोर्ड : 15 वर्ष की सेवा से पहले सेवा से पदच्यूत किस जाने वाले मामले में, अगर कर्मचारी के द्वाराचार से बोर्ड को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचता है, और विनियम १२ इबी४ के तहत रोकी गई राशि इवेष्ट अंशदान४ भी वित्तीय नुकसान के लिए काफी नहीं है, तो, ऐसे राशि को उसको भुगतान किये जाने वाले बोर्ड के अंशदान से पूरा किया जाएगा ।

इबी४ अगर वह अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति या आगे की सेवा के लिए अक्षम द्रष्टव्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित करता या स्थापना में घटौती या अन्य द्वाराचार के सिवाय कुछ वजहें या उपरोक्त खंड ४८४ में बताई गई परिस्थिति के तिवा अन्य त्याग पत्र देने की अनुमति दी गई है, तो

इसके अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ।

॥१॥ अंशदाता की मृत्यु पर भुगतान :

अंशदाता की मृत्यु पर उसके खाते की राशि से, कटौती अगर कोई हो तो उसे करके भुगतान किया जाएगा या जहाँ ऐसी राशि भुगतान करने वाली हो उसे देय हो ।

॥२॥ जब अंशदाता का परिवार हो तो -

॥१॥ अगर अंशदाता ने विनियम ६ के प्रावधानों के अनुसार उसके परिवार से एक या एक से अधिक का नामांकन दिया है तो निधि में उसके खाते में रहने वाली राशि या उसके भाग को नामिती को या नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार नामितियों को दिया जाएगा ।

॥२॥ अगर अंशदाता के परिवार का सदस्य/के सदस्यों के प्रति कोई ऐसा नामांकन नहीं है या अगर ऐसा नामांकन तिर्फ उसकी निधि के खाते की राशि के एक भाग से ही सम्बंधित है तो नामांकन उसके परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने के बावजूद भी उसके खाते की पूरी राशि या उस भाग जो नामांकन से सम्बंधित नहीं हो जो भी मामला हो, को उसके परिवार के सदस्यों के बीच सम रूप में विभाजित की जाएगी ।

बास्ते कि कोई हिस्सा निम्न लिखित को नहीं दिया जाएगा:-

॥१॥ कानूनी रूप से वयस्कता प्राप्त लड़का

॥२॥ मृतक पुत्र का बेटा का जो कानूनी रूप से वयस्कता हो गया हो

॥३॥ शादीशुद्धा लड़की जिसका पति जीवित हो, तथा

॥४॥ मृतक बेटे की शादीशुद्धा लड़की जिसका पति जीवित हो, अगर खण्ड ॥१॥, ॥२॥, ॥३॥ तथा ॥४॥ में विनिर्दिष्ट के तिवाय उसके अन्य कोई परिवार सदस्य हैं तो वह ।

बास्ते कि मृतक लड़के की विधवा या विधवार्से तथा बच्चा या बच्चों के बीच में वह समान हिस्सा ही होगा, जो, अंशदाता के जीवित होने पर लड़के द्वारा प्राप्त किया जाता तथा पहली शर्ते के खण्ड ॥१॥ के प्रावधान से छूट दी गई हो ।

टिप्पणी :

॥१॥ इन विनियमों के तहत अंशदाता के परिवार के सदस्य को देय कोई भी राशि तिर्फ उसी सदस्य को दी जाएगी जो कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा ॥३॥ की उप धारा ॥२॥ के तहत है ।

॥२॥ जब अंशदाता का परिवार न हो :

॥१॥ अगर अंशदाता का परिवार ने किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विनियम ॥६॥ के प्रावधानों के तहत नामिती बंनाया है और वह नामांकन जारी है तो उसकी निधि में जमा राशि अथवा उसका भाग जिससे कि नामांकन संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात के हिसाब से उसके नामिति/नामितियों को देय होगी ।

बोट :

॥१॥ भविष्य निधि अधिनियम 1925 के खण्ड ॥सी॥ की धारा ॥२॥ में जिसे नामिती को अंशदाता के आश्रित के रूप में बताया गया है, ऐसे नामिती को ही अधिनियम की धारा ३ की उप धारा ॥२॥ के तहत राशि दी जाएगी ।

॥२॥ जब अंशदाता का कोई पारिवार नहीं हो तथा विनियम ६ के प्रावधानों के अनुसार कोई नामिती नहीं दिया गया है या निधि के उसके खाते की राशि के सिर्फ एक हिस्से का नामांकन किया गया है, तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा ॥४॥ की उप धारा ॥१॥ का खण्ड ॥सी॥ का खण्ड ॥बी॥ तथा उप खण्ड ॥२॥ के प्रावधानों के अनुसार पूरी राशि या हिस्सा बिसका नामांकन नहीं किया गया है, पर लागू होंगा ।

॥३॥ भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा २ का खण्ड ॥सी॥ में बताए अनुसार जब कोई नामिती अंशदाता को आश्रित नहीं हो तो राशि रु. 10000 से कम हो और अगर राशि रूपर 10,000/- से ज्यादा हो तो वह राशि नामिती द्वारा उचित उत्तराधिकार प्राप्ताण पत्र, प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी ।

॥सी॥ जब अंशदाता नाबालिग नामिती को छोड़ जाता है:

ऐसा मामला जिसमें अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तथा उस समय उसका नामितियों में से एक या एक से अधिक नाबालिग है तो उनको भुगतान निम्न प्रकार से होगा :-

॥१॥ नामिती ॥नामितियों॥ को न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक बशर्ते कि भविष्य निधि राशि रूपर 10,000 तक हो ॥या पहले रूपर 10,000 अगर भुगतान की राशि रूपर 10,000 से ज्यादा हो तो ॥ नाबालिग की ओर से उसके/उनके प्राकृतिक अभिभावक या अगर कोई प्राकृतिक अभिभावक उपलब्ध नहीं हो तो अध्यक्ष द्वारा नाबालिग की राशि को प्राप्त करने योग्य दृष्टि गयी व्यक्ति को उससे अभिभावकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ही राशि दी जाएगी । नाबालिग/ नाबालिगों की ओर से जो

व्यक्ति राशि प्राप्त करता है, उसको बोर्ड के विस्तृत कोई अनुवर्ती दावे न देने से सहमत बंध पत्र द्वारा जमानतों के उस्ताधर सहित हो देना होगा । रूपर 10,000 से ज्यादा आने वाली शेष राशि को कानून के अन्तरार भुगतान किया जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि जिस मामले में प्राकृतिक अभिभावक हिन्दू चिप्ति या विधुर है, तो उसको उसके नाबालिंग बच्चों की ओर से भविष्य निधि राशि का भुगतान, राशि को देखे बिना और अभिभावकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना या अगर जिस मामले में माँ या पिता का हित उस नाबालिंग बच्चों के विस्तृद है, ऐसा ठोस प्रमाण है तो क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

लेकिन यह आवश्यक होगा कि प्राकृतिक अभिभावक की अनुपस्थिति में भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने हेतु पर्याप्त प्रत्यक्षता आधार होना चाहिए । ऐसा आधार तभी माना जाएगा जब वह वास्तविक अभिभावक के रूप में शपथपत्र देगा तथा उसकी नियती सुनिश्चित की गई है । अगर न्यायालय द्वारा अभिभावक को नियुक्त नहीं किया जाया है, तथा नाबालिंग तथा उसकी सम्पत्ति जिस व्यक्तियों के पास है, कानून के अनुसार वह वास्तविक अभिभावक है । अगर कोई व्यक्ति नाबालिंग की ओर से भुगतान का दावा करता है तो उसे शपथ पत्र द्वारा अधिक्ष को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि नाबालिंग की सम्पत्ति को वह ही सम्भाल रहा है, तथा उसकी देखभाल भी कर रहा है या अगर नाबालिंग की भविष्य निधि राशि के सिवाय कोई सम्पात्ता नहीं है तो नाबालिंग उसके साथ ही रहता है तथा उसकी देख भाल वह कर रहा है । उपर्युक्त प्रत्याभूति के साथ क्षतिपूर्ति बंध पत्र के अंतरिक्ष शपथ पत्र को भी प्रस्तुत करना है । या

१२४ वयस्क बसने के बाद नामिती द्वारा दावा करने पर राशि का भुगतान नामिती को दिया जाएगा ।

बश्ते कि हरेक मामले में विनियम 15 रुपये की टिप्पणी के अनुसार व्याज भुगतान की तारीख तक दी जाएगी या अंशदाता की मृत्यु के बाद छः माह के समाप्त तक, जो भी पहले हो वह ।

४३४ अगर निधि का अंशदाता जो बरखास्त करने या त्याग पत्र देने से बोर्ड की सेवा को छोड़ देता है, और उसे बोर्ड द्वारा बाद में पुनः निपुक्त किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देश देने के अलावा विनियम 24 के तहत उन भुगतान की गई राशि को वापस करेगा । निधि को वापस की गई राशि, जो उसकी बोर्ड की पूर्व सेवा के तहत निधि को अंशदाता की गई थी, को विनियम 24 के उप विनियम ११४ के खण्ड ४रु में विनिर्दिष्ट वार्षिक वर्ष की अवधि के रूप में ही मानी जाएगी तथा अध्यक्ष अपने विवेकानुसार उपरोक्त उप विनियम के तहत रोके गये अंशदान को पूरा या उसके अंश को उसके खाते में जोड़ेगा तथा स्कावट से पहले की गई सेवा को विनियम 12 के तहत व्यविधार्य विशेष अंशदान के प्रयोजनार्थ मासने का आदेश भी देगे ।

25. कटौतियाँ :

===== इस शर्त पर कि विनियम 11 रुपये तथा 12 रुपये के तहत बोर्ड द्वारा किए गए अंशदान की कुल राशि जिसे अंशदाता के खाते में जमा किया गया है और ऐसे अंशदान पर प्रोद्धृत कोई भी व्याज तो अधिक उससे कटौती नहीं की जाएगी । जब किसी भी अंशदाता के जगा राशि उसे देय हो जाती है तो बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के प्रति देय दायित्व को अंशदाता के खाते से काट लेगे और उस राशि का भुगतान बोर्ड को करेंगे ।

बोर्ड को उत्पन्न दायित्व के तहत "देय" शब्द में कर्मचारी द्वारा द्वारायार, न्याटर का किराया, आवास निर्माण अग्रिम का शेष, सवारी या अन्य कोई आग्रिम या अतिरेक भुगतान, कोई भत्ता, तथा छुट्टी वेतन तथा आय कर अधिनियम के तहत कटौती की जाने वाली आय कर की राशि आदि की वजह से बोर्ड को हांग वित्तीय नुकासन शामिल है ।

26. कल्याण निधि को जमा करना :

इस विनियम के तहत रोकी गई राशि को बोर्ड के कल्याण निधि खाते में जमा किया जाएगा ।

इस प्रकार कल्याण निधि में जमा की गई राशि से हरेक मामले में अध्यक्ष की स्वीकृति से वापस लिया जा सकता है ।

27. राजस्व लेखे को जमा :

पूर्ण तीन वित्तीय वर्ष के लिए अदावा किए गए भविष्य निधि भेष को हर वर्ष के अन्त में बोर्ड के राजस्व लेखे में जमा किया जाएगा ।

इस विनियम के तहत इस प्रकार राजस्व लेखे में जमा की गई राशि को अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना, व्यक्ति या व्यक्तियों को जो राजस्व लेखे में जमा करने से पहले इस राशि को ले सकते थे को वापस नहीं की जाएगी

28. भविष्य निधि अधिनियम के संदर्भ में कटौतियों:

जब निधि में अंगदाता की जमा राशि या विनियम 24 व 25 के तहत कटौतियों के बाद भेष का भुगतान करना है, तो, अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि इन विनियमों के तहत कोई कटौती नहीं है, और कोई कटौती नहीं करनी है, तब तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार भुगतान करें ।

29. पाँलिसी की सुपुर्दग्गी:

१११ अंगदाता के जीवन से संबंधित पाँलिसी को उसके द्रष्ट की सेवा से जाने या लेवा निवृत्त होने पर उसको पुनः वापस की जाएगी ।

११२ इन विनियमों के तहत अगर उस व्यक्ति को जो पागल है, कोई राशि या पाँलिसी का भुगतान करना है, तौपना है, पुनः सौंपना है या सुपुर्दग्गी करनी है तो इण्डियन ट्रूनाती आधिनियम 1912 के तहत उसके बदले में

नियुक्ति प्रबंधक को भूगतान या पुनः सौंपने या स्वपुर्दग्नि की जाएगी न कि उस पागल को ।

३३। अगर पागल की सम्पदा के लिए कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया हो तो हँडियन लूनासी अधिनियम की पारा ९५ ४।४ की शर्तों के अनुसार क्लेलठर के आदेशानुसार उस पागल की तरफ से प्रभारी व्यक्ति को पालिती का भूगतान या पुनः निर्धारण किया जाएगा । पागल की तरफ से नियुक्त उस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष उतनी ही राशि का भूगतान करेगा जितना वह उचित समझेगा और शेष राशि या उसके अंश को पागल के परिवार के ऐसे सदस्यों को जो अनुरक्षण के लिए उस पर आश्रित है को भूगतान करेगा । लेकिन इन सबको करने के पहले जिस व्यक्ति को राशि देय होगी, इन विनियमों के तहत माजिस्ट्रेट द्वारा पागल सिद्ध कराने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

30. राशि का भूगतान :

उप विनियम ३३ के तहत विशेष अंशदान तथा विनियम १२ के उप विनियम ४५ ४ के तहत अतिरिक्त राशि अगर कोई है तो उसे छोड़कर अंशदाता के खाते को समाप्त करते समय पूरा भूगतान उसको किया जाएगा या अगर उसकी मृत्यु हो गई तो, उसके नार्मती या नार्मतियों को किया जाएगा । यदि बताया गया विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि के सम्बंध में भूगतान अगर कर्मचारी जीवित है तो उसे या अगर उसकी मृत्यु हो गई तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित उसके ऐसे आश्रित या आश्रितों को किया जाएगा ।

31. भूगतान की प्रक्रिया :

अंशदाता के खाते में जमी राशि के भूगतान हेतु प्रक्रिया बन्ध पत्रों करारों को प्रस्तुत करना, घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना तथा इस विनियम के तहत आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करना आदि समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित रीति फार्म के अनुसार होगा ।

32. व्याख्या :

अगर इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो, उस पर बोर्ड द्वारा विर्यापिका होती है।

33. सरकारी आदेशों को लागू करना :

इन विनियमों के प्रावधान तथा इन विनियमों में न आने वाले मामलों को लागू करने में आदेश व सरकारी निर्णय जो सरकारी अंगदायी भविष्य नियम (भारत) 1962 में है को इन विनियमों के औपचारिक संशोधन के रूप में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी व्याख्या तथा संशोधनों का बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्णय लिया गया हो।

34. निरस्त करना तथा बयात :

भविष्य नियम तथा उपदान से संबंधित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट विनियम जो इन विनियम के लागू होने से पहले थे को इन विनियम के लागू होते ही निरस्त माने जाएंगे।

बशर्ते कि निरस्त किए गए विनियम के तहत किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई या उदारीकरण को इन विनियमों के संगत प्रावधानों के तहत बनाया या लिया या लाभ उठाया गया माना जाएगा।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंगदायी भविष्य निधि विनियम के विनियम 26 के उप विनियम १५वीं में सन्दर्भित पहली अनुसूची

अगर अंशदाता के परिवार है तो नामांकन

मैं यह निर्देश देता/पेता हूँ कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंगदायी भविष्य निधि खाते में जमा भेरी राशि को भेरी मृत्यु के बाद नीचे दिए गए भेरे परिवार के सदस्यों के बीच उनके नाम के आगे बताई गई रीति से बॉटा जाए ।

मुझे यह पता है कि इन विनियम के विनियम 12 के उप विनियम १३ और १५ के तहत स्पीकार्ड विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि इस नामांकन के लिए लागू नहीं हैं ।

नामिती या नामितियों का नाम और पता	अंशदाता के साथ रिप्रता	नामिती की आय	संचय के अंश की राशि	आकस्मिकतार्थ जिनके होने से नामांकन अमान्य होगा	अंशदाता से पहले नामिती की पूर्व मृत्यु या पूर्व कालम में विर्द्धिबिट्टा आकस्मिकतार्थों को पर जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को नामिती का अधिकार दिया जाएगा, का नाम, आय, पता और रिप्रता
—	—	—	—	—	—
११	१२	१३	१४	१५	१६
—	—	—	—	—	—

स्थान : :

तारीख : :

अंगदाता का हस्ताक्षर

४ नाम बड़े अक्षरों में

हस्ताक्षर के लिए दो भाषी : पद नाम
विभाग

1. हस्ताक्षर

पद

पता

2. हस्ताक्षर

पद

पता

— — — — —
४ लेखा विभाग के प्रयोजनार्थी

स्वीकृत

वि. स. रवं मु. ले. अ.

नोट : कॉलम 4 को भी भरा जाए ताकि पूरी राशि को खाते में ले सकें ।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट
=====

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदाधी भविष्य निधि विनियम के विनियम 26 के

उप विनियम ३३ में सन्दर्भित पहली ग्रन्तुरुची

अगर अंशदाता का परिवार नहीं है तो नामांकन

में यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं तथा यह भी निर्देश देता/देती हूँ कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदाधी भविष्य निधि खाते में जमा मेरी राशि को मेरी मृत्यु के बाद मेरा कोई परिवार न रहने से नीचे दिए गए व्यक्तियों के बीच उनके नाम के आगे बताई गई रीति से बाँटा जाए ।

मझे यह पता है कि इन विनियम के विनियम 12 के उप विनियम ३३ और ५५ के तहत स्वीकार्य विशेष अंशदान तथा अतिरिक्त राशि इस नामांकन के लिए लागू नहीं हैं ।

नामिती या	अंशदाता	नामिती	संघय	आकस्मिकताएँ	अंशदाता से पहले
नागितियों	के साथ	की	के अंश	जिनके होने से	नामिती की पूर्व
का नाम	रिश्ता	आयु	की	नामांकन	मृत्यु या जिस
और पता	यदि		राशि	अमान्य	व्यक्ति या
	कोई हो			होगा	व्यक्तियों को
	हो तो				नामिती का
					अधिकार दिया
					जाएगा, का
					नाम, पता और
					रिश्ता

स्थान : :

तारीख : :

अंशदाता का हस्ताक्षर
[नाम बढ़े अक्षरों में]

हस्ताक्षर के लिए दो ताक्षी : पद नाम
विभाग

1. हस्ताक्षर

पद

पता

2. हस्ताक्षर

पद

पता

नोट : कॉलम 4 को भी भरा जाए ताकि पूरी राशि को खाते में लें सके ।
अंशदाता जिसके नामांकन में पारिवार नहीं है ऐसा बताया है की, इस
कॉलम में यह विर्निदिष्ट करना दोगा कि परिवार के होते ही यह
नामांकन अमान्य हो जाएगा ।

[लेखा विभाग के प्रयोजनार्थ]

स्पीकृत

वित्तीय शलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अंशदायी भविष्य निधि विनियम के विनियम 3 के प्रयोजनार्थ

स्वीकृतिदाता प्राधिकारी

विनियम	प्रदत्त शक्तियों	प्राधिकारी जिसको अधिकार दिया गया है
संख्या	का विवरण	
3 ॥12॥	हर स्कावट या स्कावटों की अर्द्धा छः माह में ज्यादा न हो, को माफ करना बश्यों कि हरेक स्कावट कम से कम छः माह की लगातार सेवा के बाद हो ।	अध्यक्ष : सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार । उपाध्यक्ष : वर्ग - 2, 3 व 4 के कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार ।
12.	अंशदाता जिसकी सेवा अच्छी, सक्षम, विश्वारापात्र तथा लगातार है के खाते में विशेष अंशदान की स्वीकृति ।	अध्यक्ष : सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार । उपाध्यक्ष : वर्ग - 2, 3 व 4 के कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार ।
16.	जीवन बीमा पॉलिसियों की किश्तों के भुगतान के प्रति निधि के अंशदान से प्रयोग करने की स्वीकृति के लिए बोर्ड की भविष्य निधि के अंशदाताओं से स्वीकृत आवेदन को स्वीकृत करने ।	वि. स. ब. मु. ले. अ. : सभी विभागों के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार । अध्यक्ष

19. भविष्य निधि अंशदाता के खाते में
रही राशि से अस्थाई अग्रिम की
स्वीकृति के लिए बोर्ड का अधिकार

अधिकार	.. विभागाध्यक्ष सहित सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार
उपाध्यक्ष	.. विभागाध्यक्ष को छोड़कर सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार
विभागाध्यक्ष	.. अपने विभाग के वर्ग 1 व 2 तथा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार ।

21. राजस्व लेखे में जमा का गई राशि
को राजस्व लेखे रो संवर्धन को
भुगतान करने का बोर्ड का अधिकार
उदाहरण पूर्ण लेखे वर्ष से ज्यादा
अदावी भविष्य निधि शेष ।

अधिकार

23. भविष्य निधि से अन्तिम निकासी

अधिकार : विभागाध्यक्ष सहित सभी
कर्मचारियों के मामले में पूरा
अधिकार ।

उपाध्यक्ष : विभागाध्यक्ष को छोड़कर
सभी कर्मचारियों के मामले में पूरा
अधिकार ।

[फा.सं. पी.आर-12016/9/96-पी. ई. 1]

के. बी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 1997

G.S.R. 281 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (Contributory Provident Fund) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Madras Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MADRAS PORT TRUST

(CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby make the following Regulations in supersession of the Madras Port Trust Regulations relating to Provident Fund and Gratuity.

1. Short title:

These Regulations may be called the Madras Port Trust (Contributory Provident Fund) Regulations, 1997

2. Application:

They shall apply to all, persons appointed to the Board's service and admitted to the Madras Port Trust Contributory Provident Fund.

3. Definitions:

(1) In these regulations unless the context otherwise required:-

- (i) "Accounts officer" means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or such other officer of the Accounts Department, as may be prescribed by the Chairman.
- (ii) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963).
- (iii) "Board" means the Trustees of the Port of Madras appointed under the Act.
- (iv) Chairman, Deputy Chairman, Head of Departments shall have the meaning assigned to them under the Act.
- (v) "Contribution" means a contribution and Special Contribution made by the Board under these regulations to the Account of a subscriber.
- (vi) "Dependant" for purposes of the special contribution under these regulations means any of the following relative of a deceased subscriber to the Fund, namely a wife, husband, parent, child, minor brother, unmarried sister and a deceased son's widow and child, and where no parent of the subscriber is alive; a paternal grand parent;
- (vii) "Emoluments"
- (a) In respect of Classes I & II Officers means Pay, Leave Salary or subsistence grant as defined in Fundamental Rules of the Central Government or in the Regulations if any framed by Board whichever may be applicable and will also include non-practicing allowance granted to medical officers in lieu of private practice but does not include conveyance allowance, House Rent allowance, overtime fees, cement testing allowance, fee for supervision of floating craft, diving allowance, honorarium fees, other compensatory allowance in any form.

(b) In respect of Classes III & IV time rated employees means, Pay, Leave Salary or subsistence grant as defined in Fundamental Rules of the Central Government or in the Regulation, if any framed by the Board whichever may be applicable and includes Dearness Allowance and other allowances linked to cost index as may be allowed and reckoned from time to time for the purpose and will include the City Compensatory Allowance, but exclude House Rent Allowance, Overtime Night Weightage, extra remuneration in addition to the normal wages for work done on Sundays, Holidays and off days etc. not classified as Pay.

(c) In respect of Classes III & IV piece rated employees and shore labourers will include their actual earnings including piece rate earnings, idle time wages Equation allowance but will exclude the entire element of House Rent allowance included in the Piece Rate earnings and other allowances referred to in (b) above.

(d) For purpose of Special contribution and Additional amount payable under Regulation 12(3) and (5).

In respect of officers belonging to the Classes I and II, the expression emoluments means pay as defined in F.R. 9(21) or in the Regulation if any, framed by the Board whichever may be applicable and any other amount as may be determined and classified as Pay from time to time which the Class I or Class II Officer was receiving immediately before his/her retirement or death and will also include non-practicing allowance granted to Medical Officers in lieu of private practice.

In respect of Classes III & IV employees emoluments means Pay as defined under F.R. 9(21), Dearness Allowance and any other amount as may be classified and allowed as pay from time to time, Piece rate earnings, incentive earnings and other such payments under payment by Results Scheme wherever applicable.

Explanation: Pay for the purpose of Special contribution in respect of Piece rated employees will mean the monthly average emoluments during the 12 months immediately preceding the date of quitting service or death. Periods of absence without pay will however be excluded from calculation. The term emoluments for average emoluments shall not apply for payment of Gratuity to employees governed by the payment of Gratuity Act, 1972, in respect of whom gratuity is payable in accordance with the Act.

Note: (i) Increments accruing during leave preparatory to retirement prior to date of superannuation though not actually drawn will be treated as Pay for the purpose of Special Contribution.

(ii) In case where an employee is medically invalidated from service while on leave or dies while on leave, the increment accruing during such leave though not actually drawn will also be treated as Pay for the purpose of Special Contribution.

(iii) Increments referred to in note (i) and (ii) above means increase in Pay accruing on account of increments, revision of pay scales etc.

(viii) Employee:

The word permanent and temporary employee shall have the meaning assigned to them in the "Madras Port Trust Employees (appointment/promotions) etc., Regulations."

(ix) "Family" means:

(a) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons' widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently intimates by express notification in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded, and

(b) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons' widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber by notification in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

"Explanation" - "Child" means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber who lives with an employee and treated as a member of the family and to whom the employee has through a special will given the same status as of a natural birth.

(x) 'Fund' means the Madras Port Trust Contributory Provident Fund;

(xi) 'Leave' means any variety of leave under the Madras Port Trust Leave Regulations.

(xii) 'Sanctioning Authority' for the purpose of these Regulations shall be as prescribed in the Schedule attached to this Regulation.

(xiii) 'Service' for the purpose of the Special Contribution admissible under these regulations means continuous service of a subscriber from the date of his entertainment including all periods of authorised absence with or without allowances and also service as paid apprentice in the Board if followed by permanent service without break.

Condonation of service - any break of service for a period each not exceeding six months may ordinarily be condoned by the Chairman at his discretion provided each break is preceded by at least six months of continuous service.

(xiv) "Special Contribution" means the special contribution credited under Regulation No. 12 to the contribution account of a subscriber.

(xv) "Year" means a financial year.

(2) Any other expression used in these Regulations which is defined either in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) or in the Fundamental Rules of the Central Government or any other regulations framed by the Board is used in the sense defined therein.

4. CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF THE FUND:

(i) The fund shall be administered by the Board and shall be maintained in India in rupees.

(ii) The Board may, by resolution in writing, prescribe which of the powers conferred upon the Board by these regulations may be exercised by the sanctioning authority and may alter or cancel any such resolution.

5. PROVIDENT FUND RESERVE FUND:

(1) Whenever securities belonging to the Fund mature, or are sold, the Board shall—

(a) Credit to a reserve fund called the 'Provident Fund Reserve Fund' any gain arising on such maturity or by such sale; and

(b) To make good from the 'Provident Fund Reserve Fund' any loss that may be incurred on such maturity or by such sale.

(2) The Board shall also—

(a) make good from its Revenue Account any deficit in the 'Provident Fund Reserve Fund' if and when it occurs; and

(b) subject to the provision of sub-regulation

(c) Pay to the credit of its Revenue Account the ultimate balance in the 'Provident Fund Reserve Fund' if and when this Reserve Fund is closed.

NOTE: The above will take effect from 1st April, 1940.

(3) The maximum amount that can be retained to the credit of the Provident Fund Reserve Fund Account at any one time shall be Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only). Any excess over the limit shall be transferred to the credit of the Revenue Account.

6. NOMINATIONS:

(a) The Accounts Officer shall, as soon as may be, require every subscriber to make a nomination conferring the right to receive the amount excluding, the special contribution and additional amount admissible under sub-regulations (3) and (5) of Regulation 12 that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before the amount standing to his credit has become payable, or where such amount has become payable before payment has been made.

(b) A subscriber who, at the time of joining the Fund, has a family shall send to the Accounts Officer a nomination in the form set forth in the first Schedule in favour of one or more members of his family.

(c) A subscriber who has no family may similarly nominate a person or persons in the form set forth in the second schedule; a nomination thus made is valid only for such time as the subscriber has no family.

NOTE: In this sub-rule, unless the context otherwise requires, 'Person' or 'Persons' shall include 'a company or association or body of individuals, whether incorporated or not'.

(d) A subscriber may provide in a nomination -

(i) In respect of any specified nominee that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other member of his family, be such other member or members,

(ii) That the nomination shall become invalid in the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family:

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under Clause (1) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(e) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under Clause (i) of (d) above, or on the occurrence of any event by reason of which the nomination become invalid in pursuance of clause (ii) of (d) above, or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(f) A subscriber may in his nomination distribute the amount excluding the special contribution and the additional amount admissible under sub-regulation (3) and (5) of regulation 12 that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion.

(g) A nomination may be cancelled by a subscriber in writing and be replaced by any nomination which is permitted to be made under this regulation.

(h) A nomination becomes operative only on its being accepted by the Accounts Officer.

7. SUBSCRIBER'S ACCOUNT:

An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown:

- (i) Subscriber's subscription (compulsory and voluntary).
- (ii) Interest as provided under Regulation No.15.
- (iii) Bonus as provided under Regulation 17 on subscription.
- (iv) All advances paid and recovered and withdrawals from the fund.
- (v) Contribution.
- (vi) Interest on contribution.

8. CONDITIONS OF SUBSCRIPTIONS:

(a) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service but not during a period of suspension:

Provided that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions permissible for that period.

(b) When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the regulations of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

(c) A subscriber may at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay.

(d) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-clause (c) above by a written communication to the Accounts Officer through the head of his department before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-regulation, shall be final.

9. RATE OF SUBSCRIPTIONS:

The amount of subscriptions shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions:-

(a) It shall be expressed in whole rupees.

(b) It may be any sum so expressed either 8 1/3% (10% from 1.4.1993) or any other higher percentage rate of the emoluments.

(c) The amount of subscription so fixed by giving a month's notice to the Accounts Officer may be:

(i) reduce once at any time during the course of the year.

(ii) enhance once during the course of the year.

(iii) reduce and enhance as aforesaid provided that the amount as subscription is so reduced shall not be less than the minimum prescribed in Clause (b).

(iv) if the amount of subscription payable contain a fraction of a rupee it shall be rounded off to the nearest whole rupee.

Emoluments for the purpose of this regulation shall be calculated at the rate payable to him monthly had he been on duty.

NOTE: Should a subscriber elect to pay arrears of subscriptions in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement, shall for the purpose of this regulation, be deemed to be emoluments drawn on duty.

10. REALISATION OF SUBSCRIPTIONS:

(a) Subscriptions due shall be deducted monthly from the establishment pay bills and the deductions shall be adjusted to the credit of the Fund accounts.

Provided that in the case of the subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

(b) The amount so credited shall, after the close of each month, be posted in a Provident Fund Ledger, to be kept by the Accounts Officer, from the establishment pay bills.

11. CONDITIONS OF CONTRIBUTION:

(a) The contribution by the Board shall be 8 1/3% (10% from 1.4.1993) of the emoluments on which the subscriber has subscribed under Regulation 8 and shall be credited to his account annually before the 31st March or whenever an account is closed under Regulation 24.

Provided that if a subscriber quits service or dies during a year contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casualty.

Provided further that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the regulations not to, or does not subscribe to the Fund.

(b) should a subscriber elect to subscribe during leave his leave salary shall for the purposes of this regulation be deemed to be emoluments drawn on duty.

(c) should a subscriber elect to pay arrears of subscription in respect of a period of suspension the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement shall for the purpose of this regulation be deemed to be emoluments drawn on duty.

(d) The amount of any contribution payable in respect of a period on deputation/foreign service shall, unless it is recovered from the foreign employer, be recovered by the Board from the subscriber.

(e) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee.

12. SPECIAL CONTRIBUTION:

(1) In addition to the Board's Contribution to the fund under Regulation 11(a), a special contribution shall be credited to the account of the subscriber whose service is certified to have been good, efficient, faithful and continuous by the sanctioning authority.

(2) CONDITIONS FOR PAYMENT OF SPECIAL CONTRIBUTION:

(a) OFFICERS IN CLASSES I & II:

- i) on attainment of the age of 58 years after completing 15 years of service; or
- ii) on completion of 30 years of service or
- iii) on compulsory retirement under Regulation 5 of the Madras Port Trust (Retirement) Regulations after attaining the age of 50 years but had entered Board's service before attaining the age of 35 years or

- (iv) on voluntary retirement under Regulation 6 of Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations after attaining the age of 50 years but had entered Board's service before attaining the age of 35 years or any other voluntary retirement scheme that may be framed and applicable or
- (v) on account of certified permanent incapacity due to bodily or mental infirmity; or
- (vi) on his death or
- (vii) on account of reduction of establishment, no other suitable employment having been found to him in the Board's service.

NOTE: In respect of employees in Classes I and II Services, no special contribution will be admissible in the case of dismissal from service.

(b) OTHER SUBSCRIBERS:

When the subscriber quits service on:

- (i) attainment of the age of 58 years after completing 15 years of service or more, or
- (ii) compulsory/voluntary retirement under the Madras Port Trust Employees (Retirement) Regulations after attaining the age of 55 years and completing 15 years of service or any other voluntary retirement scheme that may be framed and as may be applicable or
- (iii) Resignation or removal from service or discharge for reasons other than misconduct after completing not less than 10 years of service or
- (iv) Dismissal from service a subscriber will be entitled for special contribution only if he has completed not less than 15 years of service.

NOTE: In such cases as well as in the cases of resignation after completing ten years of service, if the Board has suffered any monetary loss due to the misconduct of the employee, the amount of loss caused by the employee shall be deducted from the amount of special contribution payable to him or

- (v) On account of certified permanent incapacity due to bodily infirmity or
- (vi) on the abolition of his appointment on account of reduction of establishment no other suitable employment having been found for him in the Board's service; or
- (vii) on death.

(c) The Special Contribution shall not ordinarily be credited to the Provident Fund Account of a Subscriber who has been discharged for misconduct. In exceptional cases, however, in which although a particular act of misconduct has been serious enough to warrant discharge,

the subscriber's previous service has been long and consistently good, efficient and faithful, the sanctioning authority may, at its discretion order that the whole or part of the special contribution be credited to the Provident Fund Account of the subscriber.

(d) In dealing with cases for the grant of special contribution, the fulfilment of the condition, that the service rendered by the employee reached the standard good, efficient and faithful service shall not be considered a mere formality. If in any case, the scrutiny of the service record of the employee shows that his service as a whole has not reached the requisite standard, it shall be considered whether the special contribution ordinarily admissible should be credited in full or reduced or withheld altogether.

(e) Ordinarily participation in an illegal strike removes all eligibility for special contribution for services rendered prior to the illegal strike. In special cases, this regulation may be relaxed by the orders of the Chairman who shall decide what period, if any, shall be deducted from the service rendered by the subscriber for the purpose of calculating the amount of special contribution.

(3) AMOUNT OF SPECIAL CONTRIBUTION:

(1) In the case of subscriber in Classes I and II the amount of Special Contribution shall be a quarter month's of emoluments for each completed six monthly period of service subject to a maximum of 16 $\frac{1}{2}$ month's emoluments or Rs.1 lakh whichever is less provided that in the case of a subscriber who dies while in service after completing 5 years of service, special contribution of not less than 12 months emoluments shall be paid.

(ii) In the case of subscriber in Classes III and IV the amount of Special Contribution shall be a quarter month's emoluments for each completed six monthly period of service subject to a maximum of 15 month's emoluments provided that in the case of a subscriber who dies while in service after completing 5 years of service a special contribution of not less than 12 months emoluments shall be paid.

(4) ADDITION TO QUALIFYING SERVICE:

While granting proportionate special contribution to Provident Fund to an employee retiring voluntarily under Regulation 7 of Madras Port Trust Employees (Retirement) Regulations, weightage upto 5 years would be given as an addition to qualifying service actually rendered by him/her. The grant of weightage upto 5 years will however be subject to the following conditions:-

(a) In respect of Classes I and II Officers, governed by Contributory Provident Fund and opted to remain under Contributory Provident Fund Scheme the total qualifying service after giving the weightage should

not in any event exceed 33 years of qualifying service and does not take him/her beyond the date of Superannuation.

- (b) The weightage is not admissible in case of Classes III and IV employees who are compulsorily governed by the Ports liberalised definition of pay under Contributory Provident Fund Scheme and also in cases of Classes III & IV employees who opt for pension scheme and Ports liberalised definition of pay.
- (c) The weightage given will be only an addition to the qualifying service for purpose of Special Contribution to Provident Fund and not for Board's Ordinary Contribution to Provident Fund.
- (d) The grant of special contribution to Provident Fund in respect of officers retiring voluntarily shall be subject to other conditions prescribed therefor in the Madras Port Trust Contributory Provident Fund Regulations.
- (e) The grant of the above weightage will not entitle the officer to any national fixation of pay for the purposes of calculating special contribution to Provident Fund.
- (f) The weightage of 5 years referred to in this Regulation shall not be admissible in cases of those who are prematurely retired by the Board in the Public interest.
- (g) The benefit of Voluntary Retirement shall not apply to employees who retire from service for being absorbed in an autonomous body, Public Sector Undertaking, Central/State Government to which he is on deputation at the time of seeking Voluntary retirement.

NOTE: 1) In calculating the completed six monthly period of service for the purpose of this Regulation the period of any refused leave or any leave preparatory to retirement that may be granted in accordance with the service rules applicable to him after attaining the age of 58 years or after the expiry of the extension of service that may be granted to him thereafter shall be excluded.

2) When an employee is retained in service on a reduced pay and the reduction in pay is for reasons other than his own fault, or is retained in service on reduced pay after the date of his superannuation or is re-appointed on reduced pay after discharge or retirement and break in service, if any, has been condoned, the special contribution admissible under this Regulation may be calculated in respect of each period of service at the rate of pay actually drawn at the end of the respective periods if that is more favourable to him, the aggregate services of the employee reckoned for this purpose being subject to a maximum of 33 years in respect of Classes I & II Officers and 30 years in respect of Classes III & IV employees.

Broken periods of service in the higher grade will however, count for special contribution in the lower grade if it is more advantageous to the employee.

5. ADDITIONAL AMOUNT:

In the case of a subscriber, who is holding a post other than the one referred to in Section 25(1)(a) of the Act and who as a result of injuries received in the execution of his duty is permanently incapacitated for further service or killed in the execution of his duty, the Chairman may in addition to the Special Contribution credit to the Provident Fund Account of the employee, an additional amount of Rs.2,500/- in each case for payment to him or if he is dead, to such dependant or dependants of the deceased employee as may be decided in each case.

6. INTEREST:

No interest shall accrue on the special contribution and the additional amount admissible under sub-regulations (1) and (5) of this regulation.

13. PAYMENT OF GRATUITY TO THE EMPLOYEES GOVERNED BY THE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972 AND THE RULES FRAMED THEREUNDER FROM TIME TO TIME.

Employees to whom the payment of Gratuity Act, 1972, applies shall be eligible for gratuity in accordance with the provisions of the payment of Gratuity Act, 1972, (Act XXX of 1972) as amended from time to time and the rules framed thereunder from time to time subject to the following liberalisation or special contribution payable under Regulation 12 (3) whichever is more beneficial to them.

NOTE: Wages for the purpose of computing gratuity shall include all emoluments (i.e.) pay, as defined under F.R.9(21), Dearness Allowance including variable Dearness Allowance, Piece Rate earnings and other such payment under a payment by Result Scheme wherever applicable or emoluments as defined in any other regulations framed by the Board.

Provided that in respect of categories governed by Piece Rate Incentive and Payment by Result Scheme, Wage shall be computed on the average of total wages received by them for a period of 3 months immediately preceding the termination of employment.

The disbursement of gratuity payable, the manner of filling the nomination, admissibility of gratuity shall be as prescribed under the 'Payment of Gratuity Act, 1972' and the rules framed thereunder and is amended from time to time.

14. INVESTMENTS:

All moneys not immediately required for the purposes of the Fund shall from time to time be invested by and held in the name of the Board in Securities authorised by the Indian Trust Act, 1882 or in fixed deposits in the State Bank of India or in Nationalised Banks or in such investments as may be approved by Central Government from time to time and the Board may from time to time by the sale of securities, standing in its name or the realisation of fixed deposits raise such sum or sums as may be required for the purpose of the Fund.

15. INTEREST ON INVESTMENTS:

(a) With effect from 1.4.1963, interest shall be allowed by the Board on all subscriptions made by the subscriber, including the amount if any, credited during the course of the year towards proceeds of insurance policy or policies under Regulation 16 and also on the Board's contributions (excluding any special contribution) admissible under Regulation 11 together with interest thereon actually credited to the subscriber's account respectively at the same rate of interest per annum as that which shall have been earned by the Board during the previous official year upon the Provident Fund investments made under Regulation 14.

NOTE: For purpose of this regulation, the rate of interest shall be rounded off to the nearest quarter percent.

(b) Interest shall be calculated in the following manner that is to say the total (excluding fractions of a rupee) of the minimum monthly balances to the credit of each subscriber for the year or for any shorter period necessitated by the closing of an account shall be ascertained and a single month's interest for the year and proportionately for any shorter period at the appropriate rate or rates shall be calculated upon such total.

(c) The interest so calculated shall be added to the principal at the end of the official year or at the closing of the account, if closed during the course of a year;

(d) In the case of a subscriber who dies or quits service or retires during the course of a year, interest shall be paid upto the end of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable, whichever of these periods on less, at the appropriate rate fixed for the previous financial year.

Provided that where the Accounts Officer has personally satisfied himself that the delay in payment was caused by circumstances beyond the control of the subscriber and that administrative delays involved in the matter have been fully investigated and action taken, interest may be paid upto the end of one year after the month in which such amount became payable.

NOTE: In the case of subscriber who dies and the amount of his credit is not paid due to his nominee being a minor, interest shall be credited to the subscriber's account in accordance with this regulation till the date of payment or upto the end of six months after the month in which the subscriber dies whichever is earlier.

16. PAYMENT TOWARDS INSURANCE POLICIES:

Payment towards insurance policies on mutually agreed terms between the subscriber and the Board shall apply only to subscribers who before the 1st August, 1969, have been permitted for making withdrawals from the funds for payment towards Life Insurance Policies and this facility shall not be extended to any new policy after the 1st August, 1969.

17. INCENTIVE BONUS:

A subscriber to the fund who on 1.4.78 and 1.4.79 and thereafter on 1st April every year has not withdrawn any amount from his Provident Fund Account during the preceding five years or three years as the case may be will be entitled to a bonus at the rate of 1% on the entire balance at his credit on 31.3.78 and 31.3.79 and 31st March of the preceding year, thereafter.

NOTE:

- i) Payment of Bonus interest during 1978-79, the five year period to be taken into account will be the period from 1.4.74 to 31.3.79 and so on.
- ii) The period of non-withdrawal is reduced to 3 years commencing from 1st April, 1979.
- iii) The term 'withdrawal' means both refundable and non-refundable withdrawals. Withdrawal for financing insurance policies will not make subscribers ineligible for the benefit.
- iv) The bonus so calculated will be rounded to the nearest whole rupee (Fifty paise counting as the next higher rupee). This will be credited to the account of the subscriber in addition to the interest of the Provident Fund balances.
- v) The balance representing only subscriber's portion will be taken into account.
- vi) The bonus will be admissible only when a subscriber has been subscribing to the fund during the preceding 5 years/3 years except where the rules permit temporary suspension of subscription for a short period e.g. while on leave or under suspension.

(vii) The year for the purpose of calculating bonus will mean financial year. But if a subscriber joins the fund or quits service in the middle of a year, the year of joining and the year of quitting service will be deemed to be full year.

(viii) The amount of bonus will be debited to the Board's Revenue Account.

18. TRANSFER FROM/TO OTHER SERVICES:

Subject to the sanction of the Board in each case, a person who has joined the Board's service from the service of any Government, of a Railway Administration or other employer, may, if he becomes a subscriber to the Fund, have any amount standing to his credit in a Provident Fund maintained by the Government, Railway Administration or other employer on the date of his joining the Board's service, transferred to his credit in the Fund. The amount so transferred shall carry interest only, it shall not entitle the subscriber to any contribution by the Board in respect thereof.

In the event of a subscriber being permanently transferred to the services under a Government, a Railway Administration or any other employer the balance in the Provident Fund Account of the subscriber may, instead of being paid in cash be transferred to his account with the new employer and thereupon these regulations shall cease to apply to him/her.

19. ADVANCES FROM THE FUND:

A temporary advance may be granted to a subscriber, from the amount of subscription together with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund (excluding Board's contribution and interest thereon) at the discretion of the Chairman subject to the following conditions:

(1) PAYMENT OF ADVANCES for one or more of the following purposes:

(i) Illness: to pay expenses in connection with the illness or confinement or a disability of the subscriber and members of his family or any person actually dependant on him.

(ii) Obligatory expenses: to pay obligatory expenses on a scale appropriate to subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal/marriage, funerals or other ceremonies, of persons actually dependant on him;

(iii) Education: to meet the cost of higher education of the subscriber and members of his family or any person who is actually dependant on him in the following types of cases -

a) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the high school stage and

b) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is not less than three years.

iv) LEGAL: to meet cost of legal expenses incurred by the subscriber in the following types of cases:-

a) where he takes recourse to legal proceedings to vindicate his position in regard to any allegations made against him in respect of any acts done or purporting to be done by him in the discharge of his official duties; or

b) where he is prosecuted in a court of law in respect of any alleged official misconduct or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry.

Provided that no advance shall be admissible

i) where an employee takes recourse to a court of law in respect of any incidents unconnected with his position as a Board's employee.

ii) where an employee sues the Board in respect of any of his service grievances or against the imposition of any penalty on him.

v) Re-construction: to meet expenses for the reconstruction of huts or houses damaged by cyclone, floods, fire etc.

vi) For any purpose not specified: in special circumstances, if the sanctioning authority is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons not specified in these regulations and also in cases of acute distress.

(2) CONDITIONS FOR PAYMENT OF ADVANCES:

i) An advance shall not except for special reasons exceed 3 months pay or the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund whichever is less.

NOTE: The term pay occurring in this Regulation, mean emoluments as defined in Regulation 3(1)(vii).

ii) An advance shall not except for special reasons, be granted until atleast twelve months after the final re-payment of all previous advances.

iii) When an advance is sanctioned before repayment of last instalment of any previous advances is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned, and the instalment for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

20. REFEATMENT OF ADVANCE:

(a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may, direct but such number shall not be less than 12 unless the subscriber so elects or in any case, more than 36. A subscriber may at his option repay in a smaller number of instalments than that specified above. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary to admit of a fixation of such instalments.

(b) Recovery shall be made in the manner provided in Regulation 10 for the realisation of subscriptions and shall commence on the first occasion after the advance is made on which the subscriber draws emoluments, other than leave salary or subsistence grant, for a full month. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is on leave or in receipt of subsistence grant and may be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(c) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated separately for purpose of recovery.

21. WRONGFUL USE OF ADVANCE:

Notwithstanding anything contained in these regulations if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under Regulation 19 has been utilised for a purpose other than that for which drawal of the money was originally sanctioned, the amount in question shall, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered by the sanctioning Authority to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber, even if he be on leave in one or more monthly instalments not exceeding twelve as may be fixed by the sanctioning authority.

NOTE: The term emoluments as used in the regulation does not include subsistence grant.

22. INTEREST ON ADVANCE:

No interest will be credited to the account of any subscriber to whom an advance has been made on any amount for the time being debited to his account as representing an outstanding advance.

23. FINAL WITHDRAWALS FROM THE FUND:

(1) A subscriber may be sanctioned by the sanctioning authority to make final withdrawals from the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in his/her Provident Fund account subject to the conditions specified therein.

(a) HOUSING: During the service of a subscriber for one or more of the following purposes, namely for:

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence including the cost of the site proposed to be acquired from the State Housing Board/Co-operative Building Societies;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence;

Provided that the amount actually subscribed by the subscriber along with the interest thereon standing to the subscriber's credit or the actual cost of the house/flat including the cost of the site and for repayment of a loan, if any, expressly taken, in that behalf, whichever is less.

(c) purchasing a house site for building a house thereon for his/her residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

Provided that the loan was taken not more than twelve months before the date of receipt of the said application.

Provided further that the amount of the withdrawal shall not exceed one half of the amount actually subscribed by him along with the interest thereon standing to his/her credit in the Fund, or the actual cost of the site whichever is less.

CLARIFICATION: The actual expenditure incurred in connection with the sale or transfer and execution of deeds may be reckoned as part of the cost of the site.

(d) constructing a house on a site purchased under Clause (c):

Provided that the amount of withdrawal for the purpose shall not exceed the balance of amount actually subscribed, by him/her together with interest thereon standing to the credit of the subscriber or the actual cost of construction of the house whichever is less.

(e) additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber without assistance from the Fund or other Government Sources;

Provided that the amount of the withdrawal does not exceed the cost thereof or the amount actually subscribed by him along with interest thereon or Rs.10,000/- whichever is less.

NOTE:

1. While sanctioning withdrawals under these regulations the sanctioning authority should satisfy himself that the size and the cost of the house/flat/site are not disproportionate to:

- 1) the status of the subscriber concerned and
- 2) the resources available in his/her Provident Fund account.
- 3) that the amount is actually required for the purpose of purchasing the house/flat/site or for repayment of a loan expressly taken for the purpose as the case may be, and
- 4) that the subscriber will acquire full title to the house/flat/site proposed to be purchased.

2. Withdrawal under sub-clause (a) or (e) of Clause (A) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

3. Withdrawal under sub-clauses (a), (d) or (e) of Clause (A) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the house where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

4. In the case of construction of a house/flat under sub-clause (a) or (d) the withdrawal will be permitted only in equal instalments (not less than two and not more than four in number), the instalments after the first being authorised by the sanctioning authority on the basis of the progress of construction of the house/flat.

5. The construction of the house should be commenced within six months of withdrawal of money and should be completed within a period of two years from the date of the commencement of construction.

The sanctioning authority may, at his discretion, relax the limit of six months prescribed above to one year.

6. If the amount is withdrawn either wholly or partly for the purpose of repayment of a loan previously raised for the purpose of purchasing or redeeming of the house/flat under sub-clause (d), the loan should be liquidated within three months of withdrawal.

7. The withdrawal may be allowed in one instalment in cases of outright purchase of a house site or for repayment of a loan earlier taken for the purpose, and in not more than three instalments if payment for the site is to be made on a n instalment basis.

8. The house-site shall be purchased within a period of one month of the withdrawal or the withdrawal of the first instalment as the case may be. In fulfilment of this condition, the sanctioning authority may require the production of receipts issued by the seller, the house building society, etc., in token of the amount of withdrawal/installment having been utilised for making payment towards purchase of the site.

9. A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Works, Housing and Supply for the grant of advances for house building purposes or has been allowed any assistance in this regard from any other Government or Port Trust source shall be eligible for the grant of final withdrawal under this regulation for the purpose specified therein:

Provided that the sum withdrawn under this regulation together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government source or Port Trust source shall not exceed the maximum limit that may be prescribed from time to time under the aforesaid scheme.

10. In the case of acquisition of a house/flat/site from the State Housing Board/Co-operative Building Societies, withdrawal will be permissible of the actual amount subscribed along with interest thereon in order to make:

- i) the initial payment on allotment of a house/ flat and
- ii) one lumpsum payment to the Housing Board later while in service to reduce the instalment dues or to liquidate the balance instalment dues.

11. The house/flat/site proposed to be acquired or redeemed by the subscriber with the help of the amount withdrawn as aforesaid shall be situated at the place of his duty or at his/her intended place of residence after retirement.

12. Withdrawals will be permitted for building, acquisition or redemption of one house or site only:

Provided the employee does not already own a house/site at the place of his/her duty or at his/her intended place of residence after retirement.

13. The subscriber who avails of the above withdrawals shall execute an agreement and submit declarations in the form and manner as may be prescribed for the above purpose.

14. Only one withdrawal shall be allowed under this sub-regulation for purposes of housing.

15. The subscriber shall submit a report in the prescribed form to the sanctioning authority on or before the 31st December in each year so long as he is in the Board's service that the house/flat/site remains in his sole ownership and that he has not parted with the possession thereof by way of Transfer, Sale, Mortgage,

Gift, Exchange, Lease, for a term exceeding three years or otherwise howsoever without the previous permission of the sanctioning authority in writing. He/She shall also submit if required the tax receipts, title deed etc. The amount withdrawn shall become repayable in one instalment with interest thereon at the appropriate rate or rates fixed from time to time under Regulation 15 from the month of such withdrawal by the subscriber, if the house is sold or gifted or exchanged or mortgaged or leased for a term exceeding three years at any time before retirement without the sanctioning authority's previous permission. In default, it shall be ordered by the sanctioning authority that the amount be recovered from the subscriber's emoluments either a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be decided by the sanctioning authority.

(B) After completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier for one or more of the following purposes.

(a) EDUCATION:

for meeting the cost of higher education of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:-

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School Stage;

Provided that the course of study is not less than three years.

The amount will be limited to 3 months pay but in no case shall the amount exceed the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

The withdrawal will not be permissible more than once every six months.

The subscriber concerned should satisfy the sanctioning authority within a period of six months from the date of withdrawal of the amount that it has been utilised for the purpose for which it was intended.

Notwithstanding provisions in Sub-Clause (i) and (ii) of Sub-Regulation (2) of this Regulation, in case where a portion of the money withdrawn by the subscriber is not likely to be spent within six months of the date of withdrawal and the subscriber contemplates making a further withdrawal during the following half year, he may, by notifying in writing to the sanctioning authority, before the expiry of the said period of six months, adjust the excess amount in the proposed withdrawal provided that such excess amount is not more than 10 percent of the amount utilised and action to withdraw further amount is taken within one month of the expiry of six months period.

(b) BETROTHAL/MARRIAGE:

For meeting the expenditure in connection with the betrothal, marriage of the subscriber or his daughter(s) or his son(s) and any other female/male relation actually dependent on the subscriber.

The amount of withdrawal in respect of each marriage will be the amount actually subscribed by the employee along with the interest thereon standing to his credit, or ten months pay for daughter/female dependant or six months pay for son/male dependant in cases of Classes I & II Officers as the case may be whichever is less and ten months emoluments for daughter/female dependant or six months emoluments for son/male dependant in other cases as the case may be whichever is less.

NOTE: i) For the purpose of this Regulation the word 'Marriage' includes 'betrothal ceremony' also

- ii) The betrothal ceremony and 'marriage ceremony shall be treated as separate purposes. A subscriber who has withdrawn on the occasion of 'betrothal ceremony' is eligible to make another final withdrawal on the occasion of 'marriage ceremony' also.
- iii) If two or more marriages are to be celebrated simultaneously, the amount admissible in respect of each marriage will be determined as if the withdrawals are sanctioned separately one after the other.
- iv) The withdrawal will be allowed not earlier than three months preceding the month in which the marriage actually takes place.
- v) In respect of the same marriage, a subscriber may either withdraw the money in terms of this regulation or draw temporary advance under Regulation 19.
- vi) The subscriber should submit a report to the sanctioning authority within a period of one month from the date of marriage or if he is on leave, within one month on return from leave, that the money withdrawn has actually been utilised for the purpose for which it was intended.

(c) ILLNESS:

For meeting the expenditure for prolonged illness of the subscriber or any person actually dependant on the subscriber.

The amount of withdrawal will be the amount actually subscribed by the subscriber along with interest thereon standing to the credit of the subscriber or 6 months emoluments whichever is less.

The subscriber should submit a report to the sanctioning authority within a period of one month from the date of withdrawal of the amount that it has been utilised for the purpose for which it was drawn.

C. PURCHASE OF MOTOR CAR/MOTOR CYCLE/SCOOTER ETC.

After completion of 15 years of service (including the broken periods of service, if any) of a subscriber or 5 years prior to attaining the age of superannuation, withdrawal may be permitted for purchasing a motor car/motor cycle/scooter or for repaying a loan already taken by the subscriber for this purpose, subject to:

- i) The subscriber's basic pay should be Rs.3,500/- per month or more in the case of purchase of motor car and Rs.1,500/- per month or more in the case of motor cycle/scooter etc.
- ii) The amount of withdrawal is limited to Rs.50,000/- for purchase of motor car and Rs.8,000/- for purchase of motor cycle/scooter etc. or the amount standing to the subscriber's credit whichever is less.
- iii) Such a withdrawal shall be allowed only on one occasion.
- iv) In the case of withdrawal for purchase of another motor car/motor cycle/scooter, advances for the purpose under the scheme for purchase of motor car/motor cycle/scooter will not be admissible.
- v) The motor car/motor cycle/scooter should be purchased within one month of the withdrawal of the money and proof of purchase should be produced to the satisfaction of the sanctioning authority failing which the entire amount is refundable to the fund together with interest at the appropriate rate as fixed under Regulation 15.
- vi) The subscriber shall submit a report to the sanctioning authority every year as long as the subscriber is in the Board's service that the motor car/motor cycle/scooter remains in his sole ownership. He shall not sell, mortgage or transfer the car/motor cycle/scooter without the previous permission of the Chairman and in case it is so parted with the amount of withdrawal shall be refunded to the credit of the subscriber's Provident Fund together with interest at the appropriate rate as fixed under Regulation 15.
- vii) The subscriber who avails of the above withdrawal shall give an undertaking to the sanctioning authority on a stamp paper.

D. 90% WITHDRAWAL:

A subscriber may be permitted to withdraw within 12 months before the date of retirement an amount not exceeding 90% of the amount standing to the credit of the subscriber payable to him from the Fund without linking to any purpose.

(2) CONDITIONS FOR FINAL WITHDRAWALS:(1) REDEPOSITION:

Any sum withdrawn at any one time for one or more purposes specified under this Regulation from the fund which is found to be in excess of that actually required by the subscriber/unutilised for the purpose should be redeposited forthwith into the Fund together with the interest due thereon at the appropriate rate or rates fixed from time to time under Regulation 15.

(ii) REPAYMENT:

A subscriber who has been permitted to withdraw the money from the Fund at any time for one or more purposes under this Regulation shall satisfy the sanctioning authority within the specified period, that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof has not been applied for the purpose for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from subscriber's emoluments either in one lumpsum or in such number of instalments as may be determined by the sanctioning authority.

(iii) PROCEDURE AND FORMS FOR PURPOSES OF FINAL WITHDRAWAL:

The subscriber shall execute agreements, submit declarations and produce documentary evidences appropriately as required for the amount withdrawn for one or more purposes under these regulations in the manner and form as may be prescribed and directed by Chairman.

(3) CONVERSION: Any outstanding balance against the temporary advances drawn for the purpose, under Regulation 19 may, at the written request of a subscriber, be converted into a final withdrawal under this Regulation provided he had on the date of such drawal satisfied the conditions mentioned therefor.

24. CLOSING OF ACCOUNTS AND PAYMENTS:

(i) The account of each subscriber shall be closed and the amount standing to his credit shall subject to any deductions under this regulation and Regulation 25 become payable on his quitting service.

(a) When he is dismissed from the service of the Board or removed or called upon to resign on account of his conduct or inefficiency or resigns without notice or permission or when he is appointed on probation and not confirmed at the end of probationary period;

i) on his dismissal from service for grave misconduct before completing 15 years of service; or

ii) on his resignation from service within 5 years from the date of joining the fund or ceases to be an employee of the Trust otherwise than by reason of death, superannuation or a declaration by the Trust's Chief Medical Officer that he is unfit for further service or the abolition of the post or the reduction of establishment.

The Board may withhold all or any part of the amount standing to his credit in the contribution account and pay him only the balance, if any, together with the amount deposited by him as subscription and interest thereon.

Provided that, if the order of dismissal/ resignation is subsequently cancelled the amount withheld shall on his reinstatement in the service be restored to his credit in the fund.

NOTE: In the case of dismissal from service after completing not less than 15 years of service, if the Board has suffered any monetary loss on account of misconduct of the employee, the amount of special contribution that is withheld under the note to Regulation 12(b) is not sufficient to cover the monetary loss, the balance may be appropriated from the Board's contribution payable to him.

(b) when he retires from service on superannuation or voluntary retirement or on being declared unfit for further service by the Trust's Chief Medical Officer or owing to reduction of establishment (or some other cause other than misconduct) or when he is permitted to resign under any circumstances other than those mentioned in clause (a) above.

(c) when he dies.

(2) PAYMENT ON DEATH OF A SUBSCRIBER:

Subject to any deductions on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where such amount has become payable, before payment has been made -

(a) When the subscriber leaves a family -

i) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Regulation 6 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

ii) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to -

i)sons who have attained legal majority.

ii)sons of a deceased son who have attained legal majority.

iii)married daughters whose husbands are alive, and

iv)married daughters of a deceased son whose husbands are alive, if there is any member of his family other than those specified in Clauses (1) (2), (3) and (4):

Provided also that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso:

NOTE: Any sum payable under these regulations to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of Provident Fund Act, 1925.

(b) When the subscriber leaves no family.

(1) If a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 6 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE: (1) When a nominee is a dependant of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Fund Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section (2) of Section 3 of that Act.

(2) When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 6 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of Clause (b) and of sub-clause(ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident Fund Act, 1925, are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

(3) When a nominee is not a dependant of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Fund Act, 1925, the amount if it does not exceed Rs.10,000/- shall be paid to the nominee and if the amount exceeds Rs.10,000/- it shall be paid to the nominee only on production of succession certificate, probate or letters of administration.

(c) When the subscriber leaves nominees who are Minors:

In the case of subscriber who dies and one or more of whose nominees to the Fund is a minor or are minors at the time of the subscriber's death the share due to the minor(s) shall be paid

1) to the guardian of the minor(s) appointed by the Court of Law.

Provided that the Provident Fund Money to the extent of Rs.10,000/- (or the first Rs.10,000/- where the amount payable exceeds Rs.10,000/-) on behalf of the minor(s) can be made to his/their natural guardian or when no natural guardian exists, to the person considered fit by the Chairman to receive payment on behalf of the minor(s), without requiring him to produce a guardianship certificate. The person receiving payment on behalf of the minor/minors should be required to execute a bond (signed by two sureties) agreeing to indemnify the Board against any subsequent claim. The balance in excess of Rs.10,000/- if any shall be paid according to law.

Provided further that in cases where the natural guardian is a Hindu widow or Hindu widower, the payment of Provident Fund moneys on behalf of her or his minor children shall be made to her or him as the case may be, irrespective of the amount involved without production of guardianship certificate or any indemnity bond unless there is anything concrete to show that the interests of the mother or the father as the case may be are adverse to those of the minor child.

It is essential, however, that in the absence of a natural guardian there should be adequate *prima facie* grounds for making payment to the person claiming it. Such ground can exist only if he/she is shown by a sworn affidavit to be a de-facto guardian and his/her bonafides have been ascertained. Even if a guardian has not yet been appointed by the court, if the minor and his property are in the custody of some person such person is in law a de-facto guardian. The person who comes forward to claim payment on behalf of the minor should satisfy the chairman by an affidavit that he is in charge of the property of the minor and is looking after it or that if the minor has no property other than the Provident Fund money, the minor is in his custody and care. The affidavit is to be produced in addition to the indemnity bond with suitable sureties; or

(ii) to the nominee when the amount is claimed by the nominee after he or she has attained majority.

Provided that in every case interest shall be allowed in accordance with the note to regulation 15(b) till the date of payment or to the end of sixth month after the month in which the subscriber dies whichever is earlier.

(3) If a subscriber to the Fund who has been dismissed from or resigned has left the Board's service is subsequently re-employed by the Board, he shall unless the Chairman otherwise directs, repay the amount paid to him under Regulation 24. On the amount being repaid, his past service under the Board during which he subscribed to the Fund shall be taken into account in reckoning the period of five years specified in Clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 24 and the Chairman may at his discretion re-credit to his account all or any part of the contributions withheld under the said sub-regulation and also order that the service rendered prior to the break shall count for the purposes of the special contribution admissible under Regulation 12.

25. DEDUCTIONS:

Subject to the condition that no deduction shall be made in excess of the total amount of any contribution made by the Board under Regulation 11(a) and 12 (1 and 3) credited to the account of the subscriber and of any interest which has accrued on such contributions, the Chairman of the Board shall, when the sum standing to the credit of any subscriber has become payable, deduct therefrom and pay to the Board the amount due under a liability incurred by the subscriber to the Board.

The expression "due" under a liability incurred to the Board includes any monetary loss suffered by the Board due to the misconduct of the employee, rent of quarters, balance of House Building Advance, conveyance or any other advances or over payments, any allowances and leave salary and amount of Income Tax deductible under the Income Tax Act.

26. Crediting to Welfare Fund:

Sums withheld by the Board under this Regulation shall be credited to the Welfare Fund Account of the Board.

A sum credited to the Welfare Fund shall be redrawn in each case with the sanction of Chairman.

27. Crediting to Revenue Account:

All balances of Provident Fund unclaimed for more than three complete account years will, at the end of each year be credited to the Board's Revenue Account.

A sum credited to the Board's Revenue account under this Regulation cannot be without the sanction of the Chairman be refunded to the person or persons who could have drawn it any time before its credit to the Revenue Account.

28. Deductions with reference to Provident Fund Act:

When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund or the balance thereof after any deduction under Regulation 24 and 25 becomes payable, it shall be the duty of the Chairman of the Board, after satisfying himself that when no such deduction has been directed under those regulations, no deduction is to be made, to make payment as provided in Section 4 of the Provident Fund Act, 1925.

29. Assignment of Policy:

- i) The policy effected on his life by a subscriber shall be re-assigned to him on his quitting the service of the Board or on his retirement.
- ii) If the person to whom under these regulations, any amount or policy is to be paid, assigned, re-assigned or delivered is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or re-assignment or delivery will be made to such Manager, and not to the lunatic.
- iii) In case where no Manager for the estate of the lunatic has been appointed, the payment or re-assignment of the Policy may be made in terms of Section 95(1) of the Indian Lunacy Act to the person having charge of the Lunatic under the orders of the Collector. The Chairman of the Board shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the Lunatic and the balance, if any or such part thereof as he thinks fit, is to be paid for the maintenance of such members of the lunatic family as are dependent on him for maintenance. But before this is done, the person to whom the payment becomes payable under the rules will have to be certified by the Magistrate as Lunatic.

30. Payment of Amount:

Except the Special contribution under sub-regulation (3) and the additional amount if any, under sub-regulation (5) of Regulation 12, all payments accruing on the closing of the account of a subscriber shall be made to him, or if he is dead, to his nominee or nominees. In regard to the Special Contribution and the additional amount referred to above, payment shall be made to the subscriber if he is alive, or if he is dead, to such dependant or dependants of the deceased employee as may be decided by the Chairman.

31. Procedure for payment:

The procedure for payment of the amount standing to the credit of the subscriber, execution of bonds, agreements, submission of declarations and production of documentary evidences appropriately as may be required for the purposes under these regulations shall be in the manner and forms as may be prescribed by the Chairman from time to time.

32. Interpretation:

If any question arises as to the interpretations of these regulations, the same will be decided by the Board.

33. Application of Government Rules:

In applying the provisions of these regulations and in matters not dealt with in these regulations, the orders and decision of the Government contained in Government's "Contributory Provident Fund Rules (INDIA) 1962" shall subject to such exceptions and modifications as the Board may decide from time to time shall be adopted with the prior approval of the Central Government pending formal amendment, to these regulations.

34. Repeal and Saving:

On commencement of these regulations, the Madras Port Trust Regulations relating to Provident Fund and Gratuity which were in force immediately before these regulations come into force shall cease to have any effect.

Provided that any order made or action taken or liberalisation allowed under the provisions of the repealed regulations shall be deemed to have been made or taken or availed of under the corresponding provisions of these regulations.

MADRAS PORT TRUST

The first schedule referred to in Sub-Regulation (b) of Regulation 6 of the Madras Port Trust Contributory Provident Fund Regulations.

FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRIBER HAS A FAMILY

I hereby direct that the amount in my credit in the Madras Port Trust Contributory Provident Fund in the event of my death shall be distributed among the members of my family mentioned below in the manner shown against their names.

I duly understand that the nomination is not applicable to the special contribution and the additional amount admissible under sub-regulation (3) and (5) of Regulation 12 of these Regulations.

Name & address of the subscriber, or nominee,	Relationship with the subscriber, or nominee,	Age of the nominee,	Amount of the nominee's share,	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, age, address and relationship of the person or persons if any to whom the nomination shall pass in the event of his predeceasing the subscriber or on the happening of the contingency or contingencies specified in the previous column.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Station:Signature of Subscriber
(NAME IN BLOCK LETTERS)

Date:

Two witnesses to Signature, Designation:

Department:

1. Signature

2. Signature

Occupation

Occupation

Address:

Address:

(For use by the Accounts Department)

ACCEPTED

F&CAO

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount of

MADRAS PORT TRUST

The Second Schedule referred to in sub-regulation (c) of Regulation 6 of the Madras Port Trust Contributory Provident Fund Regulations.

FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRIBER H.S NO FAMILY.

I hereby declare that I have no family and direct that the amount at my credit in the Madras Port Trust Contributory Provident Fund shall, in the event of my death and my having no family then, be distributed among the persons mentioned below in the manner shown against their names.

I duly understand that the nomination is not applicable to the special contribution and the additional amount admissible under sub-Regulation (3) and (5) of Regulation 12 of these Regulations.

Name & address of the subscriber.	Relationship, if any, with the Nominee.	Age of the Nominee.	Amount of credit in the Fund.	Contingencies & Relation ship of the happening person if of which any, to whom the nomination shall pass becoming invalid.	Name, address & Relation ship of the nominee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Station:

Date:

Signature of Subscriber
(Name in Block Letters)

Two witnesses to Signature.

1. Signature:

2. Signature:

Occupation:

Occupation:

Address:

Address:

NOTE: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

(For use by the Accounts Department)

ACCEPTED

FINANCIAL ADVISER & CHIEF ACCOUNTS OFFICER.

SCHEDULE I

DELEGATING AUTHORITY FOR THE PURPOSE OF THE MAHOGI PORT TRUST
CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND REGULATIONS —
REGULATION NO. 3

Regulation Number.	Description of powers delegated.	Authority to which the power is delegated.
3(xii)	Condition of break or breaks in service for a period which not exceeding six months provided each break is preceded by at least six months of continuous service.	<u>Chairman</u> : Full powers in the case of all employees. <u>Deputy Chairman</u> : Full powers in the case of Classes II, III & IV employees.
12.	Sanction of special contribution to the account of subscriber whose service is certified to have been good, efficient, faithful and continuous.	<u>Chairman</u> : Full powers in the case of all employees. <u>Deputy Chairman</u> : Full powers in the case of Classes II, III & IV employees. <u>FACAO</u> : Full powers in the cases of Classes III & IV employees of all departments.
16.	The Board's power to sanction applications from subscribers to the Board's Provident Fund for permission to utilise the subscription to the fund towards the payment of premium on policies of Life Assurance.	Chairman.
19.	The Board's powers to grant temporary advance to the Provident Fund subscribers from the amount standing to his/her credit.	 <u>Chairman</u> .. Full powers in the case of all employees including Heads of Departments. <u>Deputy Chairman</u> .. Full powers in the case of all employees excluding Heads of Departments. <u>Heads of Departments</u> .. Full powers in the case of Classes I & II and Classes III & IV employees of their departments.
21.	The Board's power to sanction payment to those concerned from the Revenue account of sums credited thereto viz. balances of Provident Fund un-claimed for more than 3 complete account years.	Chairman.
23.	Final withdrawal from Provident Fund.	Chairman: full powers in the case of employees including Heads of Departments. Deputy Chairman: Full powers in the case of employees excluding Heads of Departments.

